सूविचार

विफलता का मौसम सफलता के बीज बोने का सर्वश्रेष्ठ समय है।

दैनिक

इंटरनल न्यूज

सच की तह तक....

internalnews@gmail.com

www.internalnews.com

वर्ष : 12 | अंक : 129 | पृष्ठ : 08 | मूल्य 1 रूपये | भोपाल, शुक्रवार 07 अगस्त 2026 | RNI NO. MPHIN/2015/61965

7वें अंतर्राष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में मध्यप्रदेश के हरित ऊर्जा मॉडल का हुआ प्रेजेंटेशन

नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य

स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवहन का दिया संदेश, सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली मेट्रो से किया सफर

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में भाग लेते हुए कहा कि मध्यप्रदेश वर्ष 2030 तक देश के 500 गीगा वॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य नवकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण तथा हरित औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। म.प्र. आज देश के अग्रणी राज्यों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन में शामिल होने के लिए एयरपोर्ट से दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के माध्यम से शिवाजी स्टेडियम तक यात्रा कर स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का संदेश दिया। दिल्ली मेट्रो अपने संचालन में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उपयोग करती है, इसलिए मुख्यमंत्री ने हरित ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में मेट्रो से यात्रा की।

नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी-2026 में मध्यप्रदेश ने स्वच्छ एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजना का प्रभावी प्रेजेंटेशन दिया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी तथा भूटान के ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री एच.ई. ल्योनपो जेम त्शेरिंग तथा श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री श्री अनुरा करुणाथिलका, अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा म.प्र. श्री मनु श्रीवास्तव सहित देश-विदेश के ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ, नीति-निर्माता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य में निवेश-अनुकूल नीतियों, सुदृढ़ आधारभूत संरचना और पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से मध्यप्रदेश देश के अग्रणी ग्रीन एनर्जी हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। यह आयोजन स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने तथा सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मध्यप्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 438 मेगावॉट से बढ़कर 11,000 मेगावाट हो गई है, जो लगभग 25 गुना वृद्धि है। पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने नवकरणीय ऊर्जा, पंप्ड हाइड्रो ऊर्जा भंडारण तथा बायोमास नीतियां लागू कर निवेश और नवाचार को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना ने देश में पहली बार सौर ऊर्जा का टैरिफ कोयला आधारित विद्युत से भी कम स्थापित किया। इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेन्ट्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस प्राप्त हुआ तथा इसकी केस स्टडी हावर्ड युनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। वहीं 1,500 मेगावाट आगर-शाजापुर-नीमच सौर परियोजना में 2.14 रूपये प्रति यूनिट का रिकॉर्ड न्यूनतम सौर टैरिफ प्राप्त हुआ है और इससे भारतीय रेलवे को 8 राज्यों में हरित ऊर्जा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 278 मेगावॉट क्षमता की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। इसके साथ ही सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के अंतर्गत लगभग 14,900 मेगावॉट क्षमता के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें किसानों और एमएसएमई क्षेत्र की उल्लेखनीय भागीदारी रही है।

संक्षिप्त समाचार

मकान ढहने से एक परिवार के छह लोगों की मौत

प्रतापगढ़। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में लगातार बारिश के बीच गुरुवार भोर को कोतवाली नगर क्षेत्र के महुली वार्ड में करीब 100 साल पुराने जर्जर मकान के ढहने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई। हादसे में परिवार का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद प्रशासन ने पीड़ित परिवार को कुल 26.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। प्रारंभिक जांच में लगातार हो रही बारिश को जर्जर मकान के ढहने की संभावित वजह माना जा रहा है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। मकान की छत अचानक भरभराकर गिरने से प्रमोद श्रीवास्तव, उनकी प ी रीता श्रीवास्तव, बेटे नितिन श्रीवास्तव, बहू माधुरी श्रीवास्तव और दो मासूम बच्चों माधव व अद्विक की मलबे में दबकर मौत हो गई। परिवार के बड़े बेटे अमन श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मकान गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाकर दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए कई घंटे तक अभियान चलाया गया। छह लोगों को बचाया नहीं जा सका, जबकि घायल अमन श्रीवास्तव को तत्काल अस्पताल भेजा गया। जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और राहत कार्यों की जानकारी ली।

एटीएफ में इथेनॉल मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं, अफवाहों से बचें: केंद्र सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विमानन ईंधन (एविएशन टर्बाइन फ्यूल-एटीएफ) में इथेनॉल मिलाने संबंधी खबरों को पूरी तरह निराधार और गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा कि सरकार यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और हवाई सुरक्षा से जुड़ी गलत सूचनाएं अनावश्यक भय पैदा करती हैं। मंत्री ने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं। एसएएफ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) द्वारा मान्यता प्राप्त ईंधन है, जो कठोर तकनीकी परीक्षणों और वैश्विक सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने के बाद ही उपयोग में लाया जाता है। इसलिए दोनों ईंधनों को एक-दूसरे के समान बताना भ्रामक है। सरकार का यह स्पष्टीकरण आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के उन बयानों के बाद आया, जिनमें उन्होंने दावा किया था कि केंद्र सरकार भविष्य में एटीएफ में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि सरकार पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक करने तथा बाद में डीजल में भी एथनॉल मिलाने पर विचार कर रही है।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष को शर्तों में और ढील नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत की शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी जमानत की शर्तों में और राहत देने का अनुरोध किया था। मिश्रा के वकील ने कोर्ट से कहा कि मौजूदा प्रतिबंधों के कारण वह अपनी बेटियों के जन्मदिन कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि फिलहाल इस अनुरोध पर विचार करने का कोई आधार नहीं है और आवेदन खारिज कर दिया। बता दें यह हिंसा 3 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया गांव में उस समय हुई थी, जब किसान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

पूनावाला ने झारखंड आंदोलन की सराहना कर कहा- यह है असली लोकतांत्रिक प्रदर्शन

नई दिल्ली। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रदर्शनकारियों की खुलकर सराहना की है। उन्होंने रांची में चल रहे आंदोलन को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण विरोध का उदाहरण बताते हुए कहा कि यह असली प्रदर्शन है, जिसमें किसी प्रकार की राष्ट्रविरोधी या भड़काऊ गतिविधियां देखने को नहीं मिलीं। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी अपने संदेश में पूनावाला ने कहा कि झारखंड के प्रदर्शनकारियों ने बिना किसी विवादित नारेबाजी के अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से सामने रखा है। उन्होंने लिखा कि आंदोलन के दौरान न तो आजादी के नारे लगे, न अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग की गई और न ही हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की गई।

छात्र आंदोलन को लेकर बोले खड़गे- हर राज्य में छात्रों के साथ खड़े

नई दिल्ली। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रति समर्थन जताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल झारखंड ही नहीं, बल्कि देश के किसी भी हिस्से में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके मुद्दों के लिए आवाज उठाती रहेगी।

मीडिया से बात करने के दौरान गुरुवार को खड़गे से झारखंड के

छात्र आंदोलन पर प्रश्न पूछा गया तो उत्तर में उन्होंने कहा, कि चाहे झारखंड हो, पंजाब, दिल्ली या देश का कोई अन्य राज्य, कांग्रेस हर जगह छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान संवाद और जवाबदेही से होना चाहिए, न कि बल प्रयोग से।

खड़गे ने इस दौरान संसद में जारी गतिरोध का भी उल्लेख करते हुए कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के पक्ष में है, लेकिन इसके लिए सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने मांग दोहराई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छात्रों पर कथित लाठीचार्ज, पैलेट गन के इस्तेमाल और आंसू गैस छोड़े जाने की घटनाओं पर संसद में आकर विस्तृत बयान दें।

डांगावास हत्याकांड के सभी 40 आरोपी बरी, 11 साल बाद आया फैसला चिंताजनक: गहलोत

जयपुर। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने नागौर डांगावास हत्याकांड में कोर्ट के फैसले को बेहद चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि 11 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बावजूद इंसाफ नहीं मिलना जांच और अभियोजन की गंभीर खामियों की ओर इशारा करता है। उल्लेखनीय है कि नागौर जिले के विशिष्ट न्यायालय ने डांगावास हत्याकांड के सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें साल 2015 में इस हत्याकांड में जमीन विवाद को लेकर पांच दलितों की हत्या कर दी गई थी। गहलोत ने कहा कि नागौर के डांगावास हत्याकांड में 11 साल बाद आया फैसला बेहद चिंताजनक है। 2015 में जमीन विवाद में पांच दलितों समेत छह लोगों की निर्मम हत्या हुई थी और अब एससी-एसटी विशेष कोर्ट ने सभी 40 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। पीड़ित परिवारों का सवाल जायज है, अगर 40 आरोपी बरी हो गए तो इन छह लोगों की हत्या आखिर किसने की?

न्यायिक अधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं, उनकी अलग श्रेणी: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भले ही संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्य सरकारें करती हों, लेकिन उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारी एक विशिष्ट और अलग श्रेणी (सेपरेट क्लास) के अधिकारी हैं, इसलिए उनकी सेवा शर्तों और सेवानिवृत्ति आयु को सामान्य सरकारी कर्मचारियों के समान नहीं माना जा सकता।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे, जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव पर विभिन्न राज्य सरकारों की आपत्तियों पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान अदालत ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) सिद्धार्थ भटनाकर ने अदालत को बताया कि कुछ राज्य सरकारों का तर्क है कि यदि न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई जाती है, जबकि राज्य के अन्य सरकारी कर्मचारी पहले सेवानिवृत्त होते हैं, तो इससे समानता का प्रश्न उठ सकता है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तुलना उचित नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियां सामान्य सरकारी कर्मचारियों से अलग होती हैं।

राहुल गांधी का दावा- महिला प्रदर्शनकारियों के घर भेजे गए गुंडे

आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया

नई दिल्ली। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्रालय को न सिर्फ जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बल्कि जवाबदेही की मांग को लेकर फायर मोड में हैं। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई छात्रों के ऊपर दिल्ली की कार्रवाई और देश के अन्य शहरों की कार्रवाई के मामले में राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ मुंबई की चर्चित प्रदर्शनकारी और अन्य प्रदर्शनकारी भी मौजूद थे।

राहुल गांधी ने कहा कि अलग-अलग राज्यों से आए युवा प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी बैठक हुई। उन्होंने हजारों प्रदर्शनकारियों को बधाई देते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान उन्होंने किसी के खिलाफ हिंसा नहीं की। प्रदर्शनकारियों को धमकाया गया और उन पर लाठीचार्ज किया गया। मुझे आप सभी पर गर्व है। आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 15 साल की बच्ची के घर पर गुंडे भेजना और इससे माफी मंगवाना बिल्कुल भी सही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि यह बच्चे बहुत हिम्मत कि बात कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी या अमित शाह में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह ऐसे मीडिया के सामने आ कर बात कर सकें।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि मैं वह लड़की हूं, जिन्होंने 20 बच्चों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए जाने से रोका था। मीडिया से अपील है कि आप अपना नैरेटिव बदलें। लेकिन जो भी मैंने किया, उसकी वजह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। यह एक अपराध है, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने सोशल मीडिया पर मेरे बारे में पोस्टर लगाकर गलत गलत बोल रहे हैं कि मैं 140 रुपए में अपनी बॉडी बेच रही हूं। उनके दिमाग में कितनी गंदगी है, जो यह बोल रहे हैं।

संसद

वित्त मंत्री बोलीं- लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाया गया विधेयक

संसद से विनियोग विधेयक को मंजूरी, विपक्ष ने किया वॉकआउट

नई दिल्ली। संसद ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय को वैधानिक मंजूरी देते हुए विनियोग (संख्यांक-3) विधेयक पारित कर दिया। राज्यसभा ने गुरुवार को इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दी, जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी थी। इसके साथ ही सरकार को भारत की संचित निधि से उस अतिरिक्त खर्च के लिए धन निकालने की औपचारिक अनुमति मिल गई, जो संबंधित वित्त वर्ष में संसद द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक हुआ था। वहीं मांगो को लेकर विपक्षी

सदस्यों ने बहिर्गमन किया। राज्यसभा की कार्यवाही दिन में तीन बार स्थगित होने के बाद अपराह्न लगभग 2:45 बजे दोबारा शुरू हुई। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग (संख्यांक-3) विधेयक सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया। संक्षिप्त चर्चा के दौरान विभिन्न सदस्यों ने अर्थव्यवस्था और सरकारी व्यय से जुड़े मुद्दे उठाए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह अतिरिक्त अनुदान की मांग 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में हुए अतिरिक्त खर्च को नियमित करने के लिए लाई गई है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया है। सीतारमण ने यह भी उल्लेख किया कि पीएसी की अध्यक्षता परंपरागत रूप से विपक्ष के सदस्य करते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया में संसदीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सांसदों ने 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में बयान देने की मांग की।

मूंग खरीदी की अव्यवस्थाओं पर , जिला अध्यक्ष शिवकांत गुड्डन पांडेय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

धीमी तुलाई, लंबी कतारों और खाद-बीज की उपलब्धता का मुद्दा उठाया; किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग

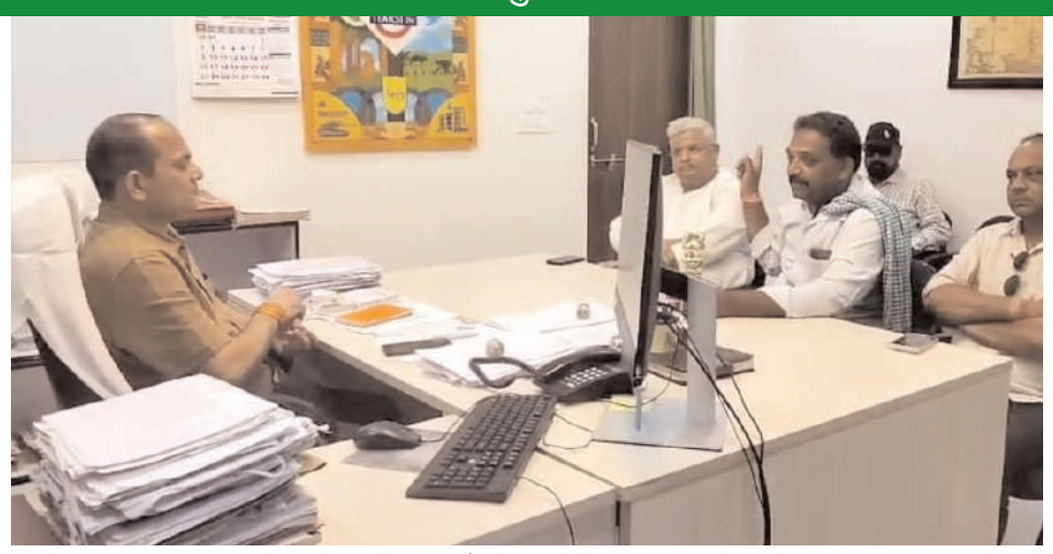

इटारसी। खरीफ सीजन में मूंग खरीदी के दौरान किसानों को हो रही परेशानियों को लेकर गुरुवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवकांत गुड्डन पांडेय के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम नीलेश शर्मा से मुलाकात कर किसानों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने मूंग खरीदी केंद्रों पर व्याप्त अव्यवस्थाओं, तुलाई में हो रही देरी तथा किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराने की मांग करते हुए शीघ्र प्रभावी कार्रवाई की मांग की।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को बताया कि जिले के विभिन्न खरीदी केंद्रों एवं वेयरहाउसों में मूंग की तुलाई अत्यंत धीमी गति से की जा रही है। इसके कारण किसानों को कई-कई दिनों तक अपनी उपज से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ इंतजार करना पड़ रहा है। खरीदी केंद्रों पर लंबी कतारें लगने से किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवकांत गुड्डन पांडेय ने कहा कि वर्तमान में बारिश का मौसम होने के कारण खुले में खड़ी मूंग की फसल खराब होने का खतरा बना हुआ है। यदि खरीदी प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई गई तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि खरीदी केंद्रों पर तुलाई की गति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन एवं कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए, ताकि किसानों को समय पर राहत मिल सके। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि खरीदी केंद्रों के बाहर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की लंबी कतारें लगने से प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इससे आम नागरिकों के साथ-साथ किसानों को भी आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी मांग की। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि एक ओर सरकार किसानों के हितों की बात करती है, वहीं दूसरी ओर खरीदी व्यवस्था की बदहाल स्थिति किसानों को परेशान कर रही है। उन्होंने मांग की कि किसानों की मूंग की उपज का शीघ्र एवं व्यवस्थित तरीके से क्रय किया जाए तथा कृषि कार्यों के लिए आवश्यक खाद एवं बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएं। एसडीएम नीलेश शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल की बात गंभीरता से सुनते हुए किसानों की समस्याओं के संबंध में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में जिला संगठन महासचिव मधुसूदन यादव, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष बाबू चौधरी, इंटक जिला अध्यक्ष शेख रमजान, जिला अनुशासन समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र मालवीय, कांग्रेस नेता हरीश मालवीय, किसान कांग्रेस जिला महामंत्री अजय पटेल, किसान कांग्रेस नगर अध्यक्ष अखिलेश पटेल, जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार, चंद्रकांत बहारे, अनूप गांचले सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रेस विज्ञप्ति जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार द्वारा जारी की गई।

तीन साल से सड़क और स्ट्रीट लाइट से वंचित कॉलोनीवासी, एसडीएम से लगाई कार्रवाई की गुहार

सईद खान सिरोंज

नगर के तिवारी पामाखेड़ी रोड स्थित गोल्डन सिटी कॉलोनी फेस-2 एवं पार्क सिटी कॉलोनी फेस-3 के रहवासियों ने कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिरोंज को ज्ञापन सौंपकर संबंधित कॉलोनाइजरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कॉलोनीवासियों ने बताया कि पिछले करीब तीन वर्षों से कॉलोनी में सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इसके कारण रात के समय पूरे क्षेत्र में अंधेरा पसरा रहता है, जिससे चोरी-डकैती जैसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है। वहीं, बरसात के दिनों में सड़क नहीं होने से आवागमन भी बेहद कठिन हो जाता है। रहवासियों का कहना है कि खराब सड़क व्यवस्था के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है तथा महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य नागरिकों को प्रतिदिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनीवासियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार संबंधित कॉलोनाइजरों रोहित शाक्य, आमिर मियां, फहीम मियां, यूसुफ एवं अयूब से सड़क और विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता रहा।

प्रतियोगी परीक्षाओं एवं भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के विरुद्ध अभाविप का राष्ट्रव्यापी संघर्ष जारी

पंजाब में शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिसिया बर्बरता दुर्भाग्यपूर्ण तथा निंदनीय; प्रशासनिक अराजकता और संवेदनहीनता से ग्रस्त है पंजाब सरकार

भोपाल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) देशभर में प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं में सामने आ रही अनियमितताओं, प्रश्नपत्र लीक तथा भर्ती प्रक्रियाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर संघर्ष कर रही है। झारखंड, कर्नाटक, पंजाब एवं बिहार सहित विभिन्न राज्यों में अभाविप लोकतांत्रिक आंदोलनों के माध्यम से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, संस्थागत सुधार तथा सरकारों एवं परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठा रही है। अभाविप का स्पष्ट मत है कि प्रत्येक परिश्रमी विद्यार्थी को न्यायपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना तथा उत्तरदायी संस्थागत तंत्र सुनिश्चित करना प्रत्येक सरकार का दायित्व है। पंजाब में अभाविप ने विधानसभा का घेराव कर प्रश्नपत्र लीक एवं भर्ती अनियमितताओं के विरोध में व्यापक प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पंजाब सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। इस दमनात्मक कार्रवाई में अनेक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कई कार्यकर्ताओं की हड्डियाँ टूटी हैं तथा कई के कान के पर्दे फट गए हैं। कर्नाटक के हुब्बली में अभाविप ने चक्कस्ट प्रकरण की छ्ब्ब्छ जांच, भर्ती अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच तथा रिक्त शिक्षकीय पदों पर शीघ्र स्थायी नियुक्तियों की मांग को लेकर विशाल प्रदर्शन किया। बिहार में पटना विश्वविद्यालय की लॉ प्रवेश परीक्षा-2026 के कथित प्रश्नपत्र लीक प्रकरण की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर सभी तथ्य सार्वजनिक करने की मांग की गई है। वहीं झारखंड में रांची महानगर इकाई ने छ्क्कस्ट एवं छ्स्स्ट परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं तथा युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के विरोध में विद्यार्थी आक्रोश मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, निष्पक्ष जांच एवं परीक्षा तथा भर्ती व्यवस्था में व्यापक संस्थागत सुधार की मांग की।

इसी क्रम में अभाविप देश के अन्य राज्यों में भी विद्यार्थियों के विभिन्न न्यायोचित विषयों को लेकर आंदोलनरत है। तेलंगाना के वारंगल में लंबित फीस प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्तियों के भुगतान की मांग को लेकर विद्यार्थी मार्च आयोजित किया गया, जिसमें अनेक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भारी फीस वृद्धि के विरोध में अभाविप ने विद्यार्थी आक्रोश रैली, शांतिपूर्ण प्रदर्शन तथा क्रमिक भूख हड़ताल प्रारंभ की है। वहीं मध्य प्रदेश में प्रस्तावित मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 का विरोध करते हुए अभाविप ने शिक्षा के बाजारीकरण को बढ़ावा देने वाले, विश्वविद्यालयों की स्थापना के मानकों में ढील देने वाले तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करने वाले प्रावधानों को वापस लेने की मांग की है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, ÷पंजाब, झारखंड, कर्नाटक एवं बिहार में अभाविप द्वारा उठाए गए विषय केवल चार राज्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देशभर के लाखों परिश्रमी विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े गंभीर प्रश्न हैं। प्रश्नपत्र लीक, भर्ती अनियमितताओं, परीक्षा प्रणाली की अपारदर्शिता तथा प्रशासनिक जवाबदेही के अभाव ने विद्यार्थियों के विश्वास को गहरी चोट पहुँचाई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन गंभीर विषयों पर संवेदनशीलता और सार्थक संवाद स्थापित करने के बजाय अनेक स्थानों पर सरकारों ने संवादहीनता का परिचय दिया तथा शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलनों को दमनात्मक कार्रवाई से रोकने का प्रयास किया। अभाविप पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, तेलांगना, बिहार सहित विभिन्न राज्यों में कार्यकर्ताओं पर हुई पुलिसिया बर्बरता की घोर निंदा करती है और स्पष्ट करती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विद्यार्थियों की आवाज़ को बलपूर्वक दबाया नहीं जा सकता। प्रत्येक परिश्रमी विद्यार्थी के न्याय, पारदर्शी एवं विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था, उत्तरदायी संस्थागत तंत्र तथा गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ शिक्षा के लिए अभाविप का लोकतांत्रिक संघर्ष निरंतर जारी रहेगा।

मार्क जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मांगी माफी

नई दिल्ली। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को लेकर चल रही बहस के बीच मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीपफेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म संचालन में हुई खामियों पर माफी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों के साथ हालिया बातचीत में उन्होंने इन मुद्दों पर खेद जताया। जानकारी के अनुसार, सरकार ने मेटा को स्पष्ट किया कि वह केवल इंटरमीडियरी की भूमिका में नहीं है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी अधिक है। प्रसारण और नेटवर्क समाचार भौगोलिक संदर्भस्टॉक और बॉन्डअपराध क्करू मोदी का वीडियो हटाने पर भी मांगी माफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने के मामले में भी मेटा ने खेद जताया है। मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलन ने कहा, ÷मैंने क्करूमोदी की पोस्ट को रोकने वाली गलती के लिए मेटा की ओर से मंत्री से माफी मांगी।÷ इससे पहले पीएम मोदी के वीडियो को हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने मेटा के अधिकारियों को तलब किया था। बाद में कंपनी ने इसे तकनीकी गलती बताते हुए वीडियो बहाल कर दिया था। इस मामले में संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने मेटा पर कड़ा रुख अपनाया था। समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा था कि अगर यह तकनीकी गलती थी तो यह बेहद गंभीर है और यदि जानबूझकर किया गया तो यह प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का प्रयास माना जाएगा। समिति ने मार्क जुकरबर्ग से व्यक्तिगत माफी की मांग की थी और चेतावनी दी थी कि जरूरत पड़ने पर सेफ हार्बर संरक्षण पर भी विचार किया जा सकता है। जुलाई में सुस्त पड़ा सेवा क्षेत्र, साढ़े चार साल की सबसे धीमी रही विकास दर, एचएसबीसी सर्विसेज पीएमआई 57.4 से फिसलकर 53.3... डीपफेक और छ्रूस्रूपर बढ़ी सख्ती बैठक में सांसदों ने डीपफेक, साइबर ठगी, महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन उत्पीड़न और छ्रूस्रूजैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाए। समिति ने सोशल मीडिया कंपनियों से आपत्तिजनक सामग्री पर समयबद्ध कार्रवाई और एल्गोरिदम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा। अब जुकरबर्ग की माफी के बाद नजर इस बात पर है कि संसदीय समिति इसे पर्याप्त मानती है या आगे भी जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया जारी रखती है।

शिव शक्ति मंदिर हर्षवर्धन नगर में संगीत मय शिव महापुराण कथा, कलश यात्रा निकाली

भोपाल। आज से शिव शक्ति मंदिर हर्षवर्धन नगर में संगीत मय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है इस शिव महापुराण कथा का आयोजन 6 से 12 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है इसकी कलश यात्रा प्राचीन माता मंदिर टी टी नगर से प्रारंभ हुई एवं विभिन्न मार्गो से होती हुई शिव शक्ति मंदिर हर्षवर्धन नगर पहुंची मुख्य कथा व्यास आचार्य पंडित श्री संदीप शास्त्री जी भोपाल द्वारा किया जाएगा महापुराण कथा का आयोजन उत्सव कार्यकारिणी समिति एवं समस्त शिव शक्तिभक्त एवं हर्षवर्धन नगर वासी आयोजित कर रहे हैं

आईटीआई पदोन्नति प्रक्रिया पर उठे सवाल, सीआर विसंगतियों को लेकर कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन

भोपाल। मध्यप्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में चल रही पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर कर्मचारियों और अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। सीआर उन्नयन मंच के बैनर तले कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने कौशल विकास विभाग के संचालक को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि गोपनीय चरित्रावली (सीआर) से जुड़ी कई गंभीर विसंगतियों के बीच पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, जिससे पात्र कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि जब तक अपात्र घोषित किए गए कर्मचारियों की सीआर का निष्पक्ष पुनरावलोकन नहीं हो जाता, तब तक वर्तमान पदोन्नति प्रक्रिया को अस्थायी रूप से स्थगित रखा जाए। साथ ही सभी कर्मचारियों की सीआर तत्काल पोर्टल पर प्रदर्शित कर डाउनलोड की सुविधा उपलब्ध कराने, कोरोना काल (2021-22 एवं 2022-23) की निम्न ग्रेडिंग को पदोन्नति में बाधक नहीं मानने तथा समय-सीमा में नहीं लिखी गई सीआर का मूल्यांकन अप्रेजल के आधार पर करने की मांग भी की गई है। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि जिन कर्मचारियों को निम्न ग्रेडिंग दी गई है, उन्हें नियमानुसार इसकी सूचना नहीं दी गई, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने सीआर संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए संचालक की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पुनरावलोकन समिति गठित करने की मांग रखी है। ज्ञापन में दुर्भावनापूर्ण तरीके से सीआर लिखने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, बिना नोटिस प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने वाले अधिकारियों पर आर्थिक दंड तथा भविष्य में सीआर प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने जैसे सुझाव भी दिए गए हैं।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पदोन्नति प्रक्रिया से जुड़े अनेक अभ्यर्थी लगातार कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी उपलब्ध नहीं होने से उन्हें अपनी समस्याएं रखने और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है और पदोन्नति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।कर्मचारियों ने मांग की है कि समस्त हस्ताक्षरित कर्मचारियों की सीआर तत्काल सार्वजनिक की जाए तथा 31 अगस्त तक सीआर अपग्रेडेशन की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश जारी किए जाएं, ताकि पात्र कर्मचारियों को

एफडीडीआई छिंदवाड़ा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 9वाँ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस - डे

छिन्दवाड़ा। फुटवियर डिज़ाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) छिंदवाड़ा परिसर में आज 9वाँ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस-डे हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महर्षि विद्या मंदिर स्कूल छिंदवाड़ा की प्राचार्य सुश्री श्रद्धा श्याममोहन त्रिपाठी थीं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण तथा सरस्वती वंदना के साथ किया गया। इस अवसर पर डॉ. विनीत वर्मा ने उपस्थित अतिथियों एवं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि 5 अगस्त 2017 को लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा विधेयक पारित होने के उपरांत भारत सरकार ने एफडीडीआई को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा प्रदान किया था। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 5 अगस्त को एफडीडीआई के देशभर के सभी 12 परिसरों में आईएनआई-डे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। छिंदवाड़ा परिसर के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में विद्यार्थियों को कौशल-आधारित शिक्षा की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय में कौशल एवं हुनर ही रोजगार और सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हैं।

टीवीसी मोटर्स ने मांगी 300 एकड़ जमीन बाइक व स्कूटर यूनिट लगाने की तैयारी

उज्जैन। सीएम डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से भारत के उद्योग जगत में विक्रम उद्योगपुरी का परचम लहरा रहा है। सीमन्स, वॉल्वो-आयशर, अदाणी ग्रुप, पेप्सिको, अमूल जैसे बड़े ब्रांड के बाद अब टीवीएस मोटर्स ने बाइक एवं स्कूटर यूनिट के लिए 300 एकड़ जमीन की डिमांड की है। पहला और दूसरा फेज फुल होने के बाद अब मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) का रीजनल कार्यालय तीसरे फेस की तैयारी कर रहा है। इस बार 1 हजार हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहित करने की योजना है।

दरअसल, विक्रम उद्योगपुरी उद्योग जगत की पंसद कई कारणों से बनी हुई है। पहला सबसे बड़ा कारण यहां विकसित किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर है। बड़े प्लॉट, 24 घंटे बिजली, गैस और पानी की सुविधा यहां मौजूद है। दूसरा बड़ा कारण इस उद्योगपुरी का चारों तरफ हाईवे से घिरा होना भी है। उज्जैन के आसपास से कई स्टेट और कई नेशनल हाईवे गुजरते हैं। इनमें देवास-बदनावर, इंदौर-उज्जैन, उज्जैन-झालावाड़, उज्जैन-गरोठ, उज्जैन-जावरा शामिल हैं। यह हाईवे आगे चलकर उन हाईवे से जुड़ते हैं जो महानगरों तक जाते हैं। इसी तरह उज्जैन से देश के कोने-कोने के लिए रेल कनेक्टिविटी भी है। ऐसे में विक्रम उद्योगपुरी उद्योग जगत की पहली पसंद बनी हुई है। विक्रम उद्योगपुरी में उद्योगपतियों को बेस्ट इंफ्रा तो मिल ही रहा है, यहां श्रमिकों की उपलब्धता भी है। चूंकि अब अधिकतर प्लांट ऑटोमेटिक हैं, ऐसे में महिला कर्मचारियों की मांग भी काफी है। इसके चलते उद्योगपुरी में 1.55 हेक्टेयर क्षेत्र में 66.36 करोड़ की लागत से महिला हॉस्टल बनाया जा रहा है। यह हॉस्टल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।

गार्ड रूम, सीसीटीवी कैमरे के साथ परिसर में शॉप्स भी रहेंगी। ताकि महिलाओं को उनकी जरूरत का सामान हॉस्टल परिसर में ही मिल जाए। हॉस्टल में किचन, डायनिंग एरिया, हेल्थ सेंटर के साथ लाइब्रेरी भी रहेगी। छह मंजिला हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर पर किचन, डायनिंग एरिया, हेल्थ सेंटर, लायब्रेरी और शेष फ्लोर पर डॉरमेट्री और रूम होंगे। एक रूम में दो लोग रह सकेंगे, जबकि डॉरमेट्री की क्षमता 18 से लगाकर 28 बेड की होगी।

टीवीएस मोटर्स ने जगह मांगी है

टीवीएस मोटर्स ने स्कूटर एवं बाइक यूनिट के लिए 300 एकड़ जगह मांगी है। दोनों फेज फुल होने के बाद उन्हें इंतजार का कहा है। तीसरे फेज के लिए जमीन अधिग्रहण की योजना बनाई जा रही है। अब तक 2500 एकड़ जमीन पर उद्योग लगने का रास्ता साफ हो चुका है।

राजेश राठौर
ईडी, एमपीआईडीसी, उज्जैन।

विश्व स्तनपान सप्ताह: आंगनबाड़ी केंद्रों पर गूंजा पहला दूध, सबसे जरूरी का संदेश, माताओं को दिलाई शपथ

भैरूंदा, सीहोर। शिशु के सर्वांगीण विकास और स्वस्थ भविष्य के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन पूरे देश में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग, भैरूंदा परियोजना द्वारा क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

स्तनपान को लेकर चली गहन जागरूकता–सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं के साथ-साथ परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को भी शामिल किया जा रहा है। उन्हें स्तनपान के वैज्ञानिक महत्व, सही तरीका और मातृ-शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जा रही है।

सेक्टर सुपरवाइजर श्रीमती निर्मला मालवीय ने आंगनबाड़ी केंद्र बोरखेड़ा कला एवं गिलोर ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि जन्म के एक घंटे के भीतर नवजात को स्तनपान कराना अनिवार्य है। मां का पहला पीला गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। यही प्रकृति का पहला टीका है। इसमें विटामिन-ए और रोग प्रतिरोधक क्षमता भरपूर होती है जो 6 माह तक शिशु को संक्रमण और बीमारियों से बचाती है।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं एवं परिवारजनों को स्तनपान को बढ़ावा देने की शपथ दिलाई गई। साथ ही परिवार से अपील की गई कि वे मां एवं नवजात की देखभाल में पूरा सहयोग करें।

रैली और नारे लेखन से गांव-गांव पहुंचा संदेश–जागरूकता को जन-आंदोलन बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा नारे लेखन और जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में 6 माह तक केवल स्तनपान, ऊपरी आहार नहीं और 6 माह बाद ऊपरी आहार के साथ स्तनपान जारी रखें जैसे स्लोगन के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया।

सभी केंद्रों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भावस्था के दौरान खतरे के लक्षणों की पहचान, संस्थागत प्रसव के फायदे और स्तनपान कराने की सही स्थिति व तरीका भी बताया गया।

हर नवजात को मिले स्तनपान का लाभ- परियोजना अधिकारी–महिला एवं बाल विकास विभाग, भैरूंदा के परियोजना अधिकारी श्री विनोद कुमार दीवान ने बताया कि विभाग द्वारा सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग-अलग थीम पर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा हमारा प्रयास है कि परियोजना के एक-एक घर तक स्तनपान का संदेश पहुंचे। यदि हर मां जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू कर दे तो शिशु मृत्यु दर और कुपोषण में भारी कमी लाई जा सकती है। अभियान के अंत में सभी प्रतिभागियों को पौष्टिक आहार और स्तनपान संबंधी पर्चे भी वितरित किए गए।

स्वतंत्रता दिवस पर नगर की मेधाओं का होगा सार्वजनिक सम्मान, 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों का होगा अभिनंदन

चिकित्सा, अभियंत्रिकी एवं अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में सफल विद्यार्थियों सहित बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को मिलेगा सम्मान, 10 अगस्त तक मांगी जानकारी

इटारसी। नगर के मेधावी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने तथा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने की अभिनव पहल के तहत नगर पालिका परिषद इटारसी आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह में नगर की प्रतिभाओं का सार्वजनिक सम्मान करेगी। इस सम्मान समारोह का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना तथा अन्य छात्र-छात्राओं को भी बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है।

सम्मान समारोह में वर्ष 2026 के दौरान राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य एवं उन्नत) तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर चिकित्सा, अभियंत्रिकी एवं अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा अन्य शिक्षा बोर्डों की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भी सम्मान समारोह में आमंत्रित कर सम्मानित किया जाएगा।

नगर पालिका अध्यक्ष श्री पंकज चौरे ने कहा कि नगर की प्रतिभाओं का सम्मान पूरे शहर के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मंच पर मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किए जाने से शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण बनेगा और अन्य विद्यार्थियों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि नगर पालिका शिक्षा और प्रतिभा सम्मान जैसी जनहितकारी पहलों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री सुरेखा जाटव ने नगर के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों, विद्यार्थियों तथा अभिभावकों से अपील की है कि पात्र विद्यार्थियों की जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराएं, ताकि कोई भी योग्य छात्र या छात्रा सम्मान से वंचित न रह जाए।

यादव समाज को मिला नया सारथी- शिक्षक हरिओम यादव बने यादव समाज सेवा समिति के अध्यक्ष, समाज में जश्न का माहौल

सिरोंज। लटेरी यादव समाज सेवा समिति की ऐतिहासिक बैठक में समाज के सभी वरिष्ठजनों, युवाओं एवं गणमान्य सदस्यों ने सर्वसम्मति से युवा, शिक्षाविद् और समाजसेवी हरिओम यादव को समिति का अध्यक्ष चुनकर समाज की कमान सौंप दी। जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। समाज के लोगों ने फूल-मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया और मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इज़हार किया। अध्यक्ष बनने की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में यादव समाज के लोगों में उत्साह और गर्व की लहर दौड़ गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिओम यादव, स्वर्गीय शिक्षक चुन्नीलाल यादव के सुपुत्र हैं। अपने पिता के आदर्शों, संस्कारों और शिक्षा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने समाज के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। यही कारण रहा कि समाज ने उन पर पूर्ण विश्वास जताते हुए सर्वसम्मति से यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी।

अब इस वर्ष भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का भव्य चल समारोह हरिओम यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार जन्माष्टमी महोत्सव को पहले से कहीं अधिक भव्य, आकर्षक और ऐतिहासिक बनाया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं की सहभागिता रहेगी।

जन विश्वास अभियान की मैराथन समीक्षा: पथरोटा में एसडीएम नीलेश शर्मा और सीईओ सुमन खातरकर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा, शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर संतुष्टिपूर्ण निराकरण के बाद ही प्रकरण बंद करने के निर्देश

इटारसी। केसला-जन समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से संचालित जन विश्वास अभियान के तहत गुरुवार को ग्राम पंचायत पथरोटा में क्लस्टर स्तरीय मैराथन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम नीलेश शर्मा एवं जनपद पंचायत केसला की सीईओ सुमन खातरकर ने संयुक्त रूप से की। बैठक में ग्राम पंचायत पथरोटा के सचिव सहित जनपद पंचायत एवं विभिन्न विभागों के मैदानी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक में अधिकारियों ने सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों की विभागवार विस्तार से समीक्षा करते हुए प्रत्येक प्रकरण की स्थिति जानी। एसडीएम नीलेश शर्मा ने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही, देरी या औपचारिकता स्वीकार नहीं की जाएगी।

सीईओ सुमन खातरकर ने अधिकारियों एवं पंचायत सचिवों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें, उनकी समस्या को गंभीरता से समझें तथा मौके पर समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल पोर्टल पर शिकायत बंद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि के बाद ही प्रकरण का निराकरण दर्ज किया जाए। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यों और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे तथा विभागीय समन्वय के साथ कार्य करते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए। एसडीएम नीलेश शर्मा ने कहा कि जन विश्वास अभियान का उद्देश्य शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना है।

इसके लिए प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी को संवेदनशीलता, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने सभी विभागों को नियमित मॉनिटरिंग करते हुए शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के अंत में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शासन के निर्देशों का पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ पालन करते हुए सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का शीघ्र एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने का आश्वासन दिया।

बीईओ के निरीक्षण में पीएम श्री हाई स्कूल बरेज की खुली पोल, कम मिली छात्र उपस्थिति, शौचालय में मिला सोता हुआ कुत्ता

मध्यान्ह भोजन, स्वच्छता और रिकॉर्ड संधारण में मिलीं खामियां, प्राचार्य को जारी किए गए लिखित निर्देश

सईद खान सिरोंज

विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) सिरोंज श्री प्रतीक कुमार मेहरा ने बुधवार, 5 अगस्त 2026 को दोपहर लगभग 1:30 बजे शासकीय हाई स्कूल पीएम श्री बरेज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की व्यवस्थाओं में कई गंभीर कमियां सामने आईं, जिसके बाद प्राचार्य को आवश्यक सुधार के लिए लिखित निर्देश जारी किए गए। बीईओ श्री मेहरा ने बताया कि निरीक्षण के समय विद्यालय में सभी नियमित एवं अतिथि शिक्षक उपस्थित मिले। हालांकि छात्र-छात्राओं की उपस्थिति संतोषजनक नहीं रही। कक्षा 1 से 8 तक कुल 152 विद्यार्थियों के नाम दर्ज हैं, लेकिन मौके पर केवल 73 विद्यार्थी उपस्थित पाए गए। वहीं हाई स्कूल में दर्ज 169 विद्यार्थियों में से मात्र 45 छात्र-छात्राएं ही उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान मध्यान्ह भोजन व्यवस्था की भी जांच की गई। भोजन वितरण के समय केवल 65 बच्चे उपस्थित मिले। साथ ही निर्धारित मेनू के अनुसार भोजन नहीं मिलने सहित अन्य अनियमितताएं भी पाई गईं। जांच में यह भी सामने आया कि विद्यालय के अधिकांश प्रशासनिक एवं शैक्षणिक दायित्व स्वयं प्राचार्य ही निभा रहे हैं। अन्य शिक्षकों को जिम्मेदारियां आवंटित नहीं किए जाने के कारण विद्यालय संचालन प्रभावित हो रहा है। स्वच्छता व्यवस्था भी बेहद खराब मिली। विद्यालय के शौचालय गंदे पाए गए, उनमें पानी की व्यवस्था नहीं थी तथा एक शौचालय में कुत्ता सोता हुआ मिला, जिस पर बीईओ ने नाराजगी जताई। इसके अलावा वर्ष 2025-26 का लेखा-जोखा एवं अभिलेख विद्यालय में उपलब्ध नहीं मिले। इस पर प्राचार्य को निर्देश दिए गए हैं कि 6 अगस्त 2026 को विकासखंड शिक्षा कार्यालय में समस्त लेखा रिकॉर्ड प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

सब्जी मंडी में दुकानों की नीलामी में बड़ा झोल- आवंटित दुकानदारों को मुफ़्त में बांटी जा रही अतिरिक्त सड़क, नपा को लाखों का चपत!

सिरोंज। नगर पालिका की कार्यप्रणाली और सब्जी मंडी में दुकानों के आवंटन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मंडी में नियमानुसार दुकानों की नीलामी केवल 18 मीटर तक की जगह के लिए की गई थी। नीलामी के दौरान नियमों या विज्ञप्ति में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं था कि दुकान के सामने की सड़क या अतिरिक्त जगह भी आवंटित की जाएगी। इसके बावजूद नपा प्रशासन आवंटित दुकानदारों को सामने की सरकारी सड़क पर भी मुफ़्त में कब्ज़ा करने की छूट दे रहा है।

कम दामों में बिकीं दुकानें, राजस्व का भारी नुकसान- स्थानीय नागरिकों और विक्रेताओं का आरोप है कि यदि नपा प्रशासन नीलामी के समय ही सामने की अतिरिक्त जगह को आवंटन में शामिल करने की बात स्पष्ट कर देता, तो यही दुकानें बोली में 50-50 लाख रुपये तक बिक सकती थीं। नियमों को छिपाकर रखी गई आधी-अधूरी शर्तों के कारण नपा को भारी राजस्व का नुकसान हुआ है और दुकानें औने-पौने दामों पर बिक गईं। अब वही अतिरिक्त जगह चुनिंदा दुकानदारों को मुफ़्त में देकर जिम्मेदार अधिकारी व्यक्तिगत लाभ पहुंचाते प्रतीत हो रहे हैं।

गरीब फ़ड़ वालों पर गाज़, आंदोलन की चेतावनी–एक तरफ बड़े दुकानदारों को नियम विरुद्ध जाकर सड़क और अतिरिक्त जगह का मुफ़्त लाभ दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बरसों से रोजी-रोटी कमा रहे गरीब फ़ड़ चालकों को मंडी से बेदखल कर हटाया जा रहा है।

प्रशासन के इस दोहरे रवैये से गरीब व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

गौसंवर्धन बोर्ड की योजनाओं एवं गतिविधियों को लेकर चर्चा की

भोपाल। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के नवागत सचिव डॉ. सुदाम पी. खाड़े ने बुधवार को भोपाल स्थित पशुपालन एवं डेयरी विभाग संचालनालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा। सचिव डॉ. खाड़े ने विभाग में केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। नवाचारों के क्रियान्वयन, आवंटित बजट, लक्ष्य और वर्तमान प्रगति की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला स्तर पर दवाइयों, उपकरणों की उपलब्धता, उनकी गुणवत्ता, तथा

2012 बैच की आईपीएस अधिकारी श्रद्धा तिवारी पदोन्नत, बनी डीआईजी

भोपाल। भारतीय पुलिस सेवा में 2012 बैच की आईपीएस अधिकारी श्रीमती श्रद्धा तिवारी के पदोन्नति आदेश जारी हो गए हैं। वे अब भारतीय पुलिस सेवा के वेतन मैट्रिक्स 13 (क) में उप पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत की गई हैं।

नवनियुक्त कर्मचारी पूरी निष्ठा और लगन से कार्य करें : जल संसाधन मंत्री सिलावट

अभियंता श्री आर.आर. मीना, अधीक्षण यंत्री श्री आशीष महाजन उपस्थित थे।

मंत्री श्री सिलावट ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई दी एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि सभी नवनियुक्त कर्मचारी पूरी निष्ठा, लग्न एवं समर्पण भावना के साथ कार्य करते हुए जल संसाधन विभाग को सफलता के शीर्ष पर ले जाने में अपना पूरा-पूरा योगदान दें। उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत गत वर्षों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ हुई हैं। वर्ष 2020 से अभी तक कुल 1305 कर्मचारियों को नियुक्तियाँ प्रदान की गई है, जिनमें 952 कर्मचारियों को नवीन नियुक्तियाँ एवं 353 कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

81 नवनियुक्त विभागीय कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए

भोपाल। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने बुधवार को जल संसाधन विभाग के बोधी परियोजना कार्यालय में विभाग में नवनियुक्त 81 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रमुख अभियंता श्री विनोद देवड़ा, बोधी परियोजना के मुख्य

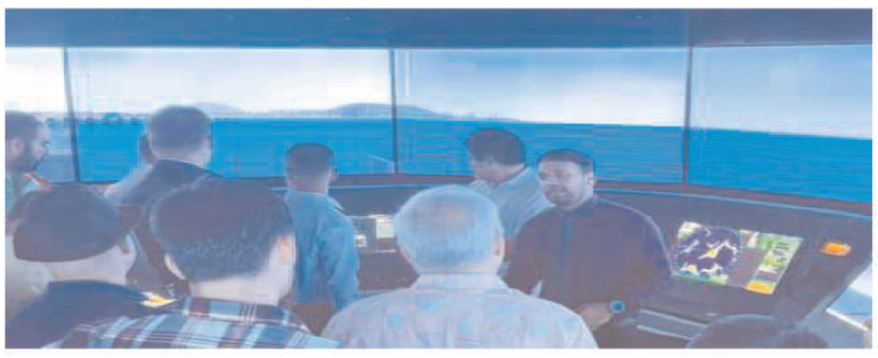

गत दिनों देश की नेशनल डिफेन्स यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में नेशनल सिक्योरिटी जर्नीलिस्म (राष्ट्रीय सुरक्षा पत्रकारिता) विषय पर आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेना का सुअवसर प्राप्त हुआ। जिसमें राष्ट्रय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे एनएसजी, कमांडो, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आरएएफ, नैवल, एनडीआरएफ के मुख्य हस्तियों से संवाद का मौका मिला. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पत्रकारिता के इस कार्यक्रम की महत्ता कार्यक्रम के समापन में पर पता चली क्योंकि ये कार्यक्रम अपने आप में अनूठा कार्यक्रम था. सम्भवत, इस विषय पर यह पहला कार्यक्रम होगा।

संपादकीय

'लोक परीक्षा बिल 2026' पास, पर क्या सच में खत्म होगी छात्रों की चिंता?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश भर में विद्यार्थियों के सड़क पर आवाज बुलंद करने के बाद हरकत में आई सरकार की ओर से प्रवेश एवं प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए लाए गए 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' को बुधवार को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। उम्मीद की जा रही थी कि विद्यार्थियों के आंदोलन से निकले इस विधेयक की अहमियत के मद्देनजर संसद में इस पर व्यापक और सार्थक चर्चा होगी, इसकी कमियों पर विचार होगा और नए सुझाव सामने आएंगे, जिनके आधार पर एक सशक्त कानून बनाया जाएगा। मगर, इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि चर्चा का यह दौर भी हंगामे की भेंट चढ़ गया, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि उसे बोलने नहीं दिया गया, वहीं सत्तापक्ष का कहना है कि विपक्षी नेताओं ने विधेयक पर चर्चा को केंद्र में नहीं रखा। विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक विद्यार्थियों पर प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग का मुद्दा लगातार उठाता रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी संकेत दिया है कि वह पुलिस की सख्ती से जुड़े मामले की जांच के लिए विशेष दल का गठन कर सकता है। काकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर शुरू हुआ विद्यार्थियों का आंदोलन तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार की ओर से परीक्षा प्रणाली में सुधार के आश्वासन के बाद ही समाप्त हुआ था। लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक इन्हीं सुधारों की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। माना जा रहा था कि इस विधेयक में अगर कोई कमी रह गई होगी, तो संसद में व्यापक चर्चा के दौरान पेश किए जाने वाले सुझावों के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है। मगर चर्चा के दौरान लोकसभा में जिस तरह का माहौल देखा गया, उससे यह विश्वास करना मुश्किल है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए वास्तव में सख्त एवं सक्षम कानून बनाने के गंभीर प्रयास हुए हों। विपक्ष की ओर से सवाल उठाना स्वाभाविक है, लेकिन यह सत्तापक्ष का दायित्व है कि वह आशंकाओं का निवारण करे और चर्चा को सही दिशा में ले जाए। अगर संसद में बिना सार्थक चर्चा के ही किसी विधेयक को पारित कर दिया जाए, तो जाहिर है कि उस पर भविष्य में भी सवाल उठते रहेंगे। दूसरी ओर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान उन पर बल प्रयोग का मुद्दा भी अहम है। यह प्रश्न शुरू से उठता रहा है कि क्या सुरक्षाबलों के लिए यही एक अंतिम विकल्प था? अगर विद्यार्थियों के संसद मार्च से पहले ही सरकार ने संवाद के जरिए उन्हें भरोसे में लेने की कोशिश की होती, तो संभवत- इस स्थिति को टाला जा सकता था। सवाल प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन और एके-47 राइफल से गोलियां चलाने को लेकर भी उठा है। खबरों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के कहने पर त्वरित कार्रवाई बल ने पैलेट गन समेत कई कम घातक हथियारों का इस्तेमाल किया था। यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच पर जोर देते हुए विशेष दल गठित करने का संकेत दिया है। साथ ही अदालत ने अठारह वर्ष से कम आयु के उन लोगों को रिहा करने का निर्देश दिया है, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बहरहाल, सत्तापक्ष हो या विपक्ष, दोनों की कोशिश यही होनी चाहिए कि देश की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार हो, ताकि विद्यार्थियों को भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

Article 370 पर बदजुबानी कर रहे थे जरदारी और शहबाज शरीफ, मोदी ने खुद आगे आकर दिया करारा जवाब

-नीरज कुमार दुबे

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सातवीं वर्षगांठ पर पाकिस्तान ने एक बार फिर पुराना राग अलापने की कोशिश की, लेकिन उसकी इस बदजुबानी का करारा जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि 5 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक फैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए एक निर्णायक नए युग की शुरुआत था। उन्होंने दो टूक कहा कि बीते सात वर्षों में इन दोनों क्षेत्रों ने विकास, सुशासन और सामाजिक सशक्तिकरण के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया, जब पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने भारत के इस संवैधानिक फैसले को लेकर फिर से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा कि सात वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 और 35ए इतिहास बन गए थे और इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के विकास का नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि वर्षों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रहे महिलाओं, अनुसूचित वर्गों और अन्य वंचित समुदायों को अब भारतीय संविधान का पूरा संरक्षण और अधिकार मिला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, उद्यमिता और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और केंद्र सरकार इन क्षेत्रों को विकसित भारत की यात्रा का मजबूत भागीदार बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस वर्ष अनुच्छेद 370 हटाए जाने की वर्षगांठ इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के वर्ष में पड़ रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए डॉ. मुखर्जी ने जिस संकल्प का सपना देखा था, वह 5 अगस्त 2019 को साकार हुआ।

दूसरी ओर, पाकिस्तान ने एक बार फिर 5 अगस्त को तथाकथित यौम-ए-इस्तेहसाल के रूप में मनाते हुए भारत के खिलाफ बयानबाजी की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने दावा किया कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को अपना नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन जारी रखेगा तथा इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहेगा।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इसी सुर में बयान देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर विवाद का समाधान पाकिस्तान की विदेश नीति का प्रमुख आधार बना रहेगा। उन्होंने भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की। वहीं उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी भारत के 5 अगस्त 2019 के फैसले को एकतरफा बताते हुए संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाने की मांग दोहराई। कुल मिलाकर देखें तो पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर वही पुराने आरोप लगाए, जिन्हें भारत लगातार खारिज करता रहा है। हालांकि पाकिस्तान की यह बयानबाज़ी इसलिए भी खोखली और दोगली नजर आती है क्योंकि जो देश कश्मीरियों के अधिकारों की दुहाई देता है, वही पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में अपने ही कब्जे वाले इलाके के लोगों पर दमनचक्र चला रहा है। हाल ही में खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पीओजेके में आंदोलन कर रहे स्थानीय लोगों को भारत की तरह पाकिस्तान का दुश्मन तक करार दिया। पीओजेके में असीम मुनीर के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिन्हें दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं, बिजली की आपूर्ति बाधित की गई, राशन और आवश्यक सुविधाओं पर भी असर पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनकी आवाज को बलपूर्वक कुचला जा रहा है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि जो पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा, वह जम्मू-कश्मीर के लोगों की चिंता जताने का नैतिक अधिकार कैसे रखता है? स्पष्ट है कि कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की राजनीति महज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रचार और दुष्प्रचार तक सीमित रह गई है। दूसरी ओर, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में विकास परियोजनाओं को तेज गति मिली है। श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जैसी वैश्विक पहचान मिली है। डल झील में संगीत फव्वारे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी ने क्षेत्र में बढ़े विश्वास और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि की है। सड़क, रेल और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, शिक्षा और उद्यमिता के नए अवसर पैदा हुए हैं तथा स्थानीय हस्तशिल्प और पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा मिली है।

बृजभूषण शरण सिंह के बाइज्जत बरी होने से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कई सारे समीकरण बदलने वाले हैं

करीब तीन वर्षों तक देश की राजनीति, खेल जगत और मीडिया के केंद्र में रहे पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) अध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को आखिरकार दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से बड़ी राहत मिल गई। महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। वैसे बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों के समर्थन में जिस तरह तमाम विपक्षी नेता खड़े हो गये थे उसके चलते यह सब कुछ शुरू से ही राजनीतिक षड्यंत्र नजर आ रहा था। उल्लेखनीय है कि जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन कराया गया था और धरने के मंच पर तमाम बड़े विपक्षी नेता पहुँचे थे और मंच से दिये गये भाषणों के जरिये भाजपा को महिला विरोधी बताया जा रहा था। साथ ही बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देशभर में माहौल बनवाने और मीडिया ट्रायल के जरिये उनकी छवि बिगाड़ने के तमाम प्रयास किये गये थे। आरोप लगाने वाले पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में बहाने तक की नौटंकी भी की थी ताकि जनता की सहानुभूति अर्जित की जा सके और हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जिताया जा सके। लेकिन साच का आंच नहीं वाली कहावत सही सिद्ध हुई और बृजभूषण सभी आरोपों से बाइज्जत बरी हो गये। विधानशाखा

हम आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह और तत्कालीन डब्ल्यूएफआई सहायक सचिव विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। इस फैसले ने न केवल तीन वर्षों से चल रहे कानूनी विवाद का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है।

उधर, फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्हें शुरू से अपने ऊपर लगे आरोपों पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि यदि आरोप सही साबित हुए तो वह स्वयं फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन आज का दिन उनके लिए प्रसन्नता का विषय है। वहीं, सरकारी पक्ष ने कहा है कि विस्तृत निर्णय मिलने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उच्च अदालत में आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

हम आपको याद दिला दें कि यह मामला अप्रैल 2023 में तब शुरू हुआ था, जब दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में छह महिला पहलवानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी दौरान एक नाबालिग की शिकायत पर पॉक्सो कानून के तहत भी अलग मामला दर्ज हुआ था। जून 2023 में दिल्ली पुलिस ने करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें चार राज्यों के 22 गवाहों के बयान शामिल थे। बाद में नाबालिग शिकायतकर्ता और उसके पिता ने अपने आरोप वापस ले लिए थे। पुलिस ने अदालत से पॉक्सो मामला समाप्त करने का अनुरोध किया था जिसे मई 2025 में अदालत ने स्वीकार कर लिया था।

मई 2024 में अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 32 गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में समय, स्थान और घटनाओं को लेकर कई बदलाव हुए तथा कुछ घटनाओं के समय आरोपी घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। बचाव पक्ष ने शिकायत दर्ज कराने में सात-आठ वर्ष की देरी का मुद्दा भी उठाया। प्रचारअभियान और चुनाव

दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष का कहना था कि पीड़िताओं के बयान मुकदमे के दौरान लगातार एक जैसे रहे और अन्य गवाहों ने भी उनका समर्थन किया। शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने अदालत में तर्क दिया कि शक्ति के असंतुलन और खेल संघ के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति के प्रभाव के कारण शिकायत दर्ज कराने में देरी स्वाभाविक थी। हालांकि, अंततः अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया। उधर, इस फैसले का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं माना जा रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला पहलवानों के आंदोलन और बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों ने भाजपा को असहज स्थिति में ला दिया था। पार्टी को विपक्ष के लगातार हमलों का सामना करना पड़ा और अंततः कैसरगंज से बृजभूषण की जगह उनके पुत्र करण भूषण सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया था। अब अदालत से बरी होने के बाद भाजपा के लिए यह फैसला राजनीतिक दृष्टि से राहत देने वाला माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब अगले वर्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।

उन्नत बचपन की पहली शर्त- स्वस्थ भोजन, स्वस्थ भविष्य

आज सबसे बड़ी चिंता यह नहीं है कि बच्चे भोजन कम खा रहे हैं, बल्कि यह है कि वे पोषण कम और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ अधिक खा रहे हैं। रंग-बिरंगे पैकेट, आकर्षक विज्ञापन, कार्टून पात्रों की ब्रांडिंग, सोशल मीडिया का प्रभाव और हर गली-मोहल्ले में उपलब्ध फास्ट फूड ने बच्चों की स्वादेंद्रियों पर ऐसा कब्जा कर लिया है कि घर का पौष्टिक भोजन उन्हें फीका लगने लगा है। यह परिवर्तन केवल खान-पान की आदत का बदलाव नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे उनके शरीर, मस्तिष्क और व्यवहार को भी प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिक शोध लगातार यह बताते रहे हैं कि अधिक वसा, अधिक नमक और अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थ बच्चों में मोटापा, उच्च रक्त चाप, मधुमेह, हृदय रोग, हार्मोन असंतुलन तथा मानसिक एकाग्रता में कमी जैसी अनेक समस्याओं का कारण बन रहे हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि जो बीमारियां पहले चालीस-पचास वर्ष की आयु में दिखाई देती थीं, वे अब किशोरावस्था और बचपन में ही दस्तक देने लगी हैं। यह केवल स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि आने वाले समय में देश की उत्पादक क्षमता और मानव संसाधन पर भी गहरा प्रभाव डालने वाला संकट है। बचपन की सबसे बड़ी आवश्यकता स्वाद नहीं, पोषण है। शरीर के विकास के साथ-साथ मस्तिष्क का तीव्र विकास भी बचपन में ही होता है। यदि इस अवस्था में बच्चों को संतुलित भोजन, ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध, दालें, मोटे अनाज और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलें, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास कहीं अधिक प्रभावी होता है।

-ललित गर्ग

विकसित भारत का स्वप्न केवल आधुनिक इमारतों, तेज अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक और विश्वस्तरीय आधारभूत संरचनाओं से पूरा नहीं होगा। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके बच्चे होते हैं। यदि बचपन स्वस्थ, संस्कारित, ऊर्जावान और मानसिक रूप से सुदृढ़ है, तो राष्ट्र का भविष्य स्वतः सुरक्षित हो जाता है। यदि बचपन ही अस्वस्थ, मोटापे, मधुमेह, कुपोषण और गलत खान-पान की आदतों से घिर जाए, तो विकास की पूरी अवधारणा खोखली सिद्ध होने लगती है। इसलिए बच्चों का स्वास्थ्य केवल स्वास्थ्य मंत्रालय का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के सभी स्कूलों और उनके आसपास जंक फूड की बिक्री, वितरण तथा प्रचार पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय इसी व्यापक दृष्टि का परिचायक है। यह केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व का गंभीर संदेश है। यह स्वीकार करने का साहसिक प्रयास है कि बच्चों की सेहत बाजार के मुनाफे से कहीं अधिक मूल्यवान है। यदि यह निर्णय प्रभावी ढंग से लागू होता है तो यह पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है।

आज सबसे बड़ी चिंता यह नहीं है कि बच्चे भोजन कम खा रहे हैं, बल्कि यह है कि वे पोषण कम और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ अधिक खा रहे हैं। रंग-बिरंगे पैकेट, आकर्षक विज्ञापन, कार्टून पात्रों की ब्रांडिंग, सोशल मीडिया का प्रभाव और हर गली-मोहल्ले में उपलब्ध फास्ट फूड ने बच्चों की स्वादेंद्रियों पर ऐसा कब्जा कर लिया है कि घर का पौष्टिक भोजन उन्हें फीका लगने लगा है। यह परिवर्तन केवल खान-पान की आदत का बदलाव नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे उनके शरीर, मस्तिष्क और व्यवहार को भी प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिक शोध लगातार यह बताते रहे हैं कि अधिक वसा, अधिक नमक और अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थ बच्चों में मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, हार्मोन असंतुलन तथा मानसिक एकाग्रता में कमी जैसी अनेक समस्याओं का कारण बन रहे हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि जो बीमारियां पहले चालीस-पचास वर्ष की आयु में दिखाई देती थीं, वे अब किशोरावस्था और बचपन में ही दस्तक देने लगी हैं। यह केवल स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि आने वाले समय में देश की उत्पादक क्षमता और मानव संसाधन पर भी गहरा प्रभाव डालने वाला संकट है। बचपन की सबसे बड़ी आवश्यकता स्वाद नहीं, पोषण है। शरीर के विकास के साथ-साथ मस्तिष्क का तीव्र विकास भी बचपन में ही होता है। यदि इस अवस्था में बच्चों को संतुलित भोजन, ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध, दालें, मोटे अनाज और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलें, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास कहीं अधिक प्रभावी होता है। इसके विपरीत जंक फूड क्षणिक स्वाद तो देता है, लेकिन शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं देता। परिणामस्वरूप बच्चा बाहर से स्वस्थ दिखाई देता है, किंतु भीतर से अनेक पोषण संबंधी कमियों का शिकार बनने लगता है। दुर्भाग्य यह है कि जंक फूड आज केवल भोजन नहीं रहा, बल्कि एक आक्रामक व्यावसायिक संस्कृति बन चुका है। विज्ञापनों के माध्यम से बच्चों के मन में यह धारणा बैठा दी गई है कि आधुनिकता का अर्थ पैकेटबंद भोजन है। लोकप्रिय खिलाड़ी, फिल्मी कलाकार और डिजिटल प्रभावक अनजाने में बच्चों को ऐसे उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं, जिनका अत्यधिक सेवन उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में केवल परिवारों को दोष देना उचित नहीं होगा। सरकार, उद्योग, विद्यालय, अभिभावक और समाज-सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि जीवनशैली का निर्माण करने वाली प्रयोगशाला भी हैं। यदि स्कूल परिसर में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए, पोषण शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, विद्यालयों में रसोई बाग विकसित किए जाएं, बच्चों को स्वयं पौधे लगाने और प्राकृतिक भोजन के महत्व से जोड़ा जाए, तो यह परिवर्तन अधिक स्थायी होगा। केवल प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। स्वस्थ विकल्पों को स्वादिष्ट, आकर्षक और सुलभ बनाना भी उतना ही आवश्यक है। भारत की पारंपरिक भोजन संस्कृति विश्व की सबसे संतुलित और वैज्ञानिक भोजन प्रणालियों में मानी जाती है। बाजरा, ज्वार, रागी, दालें, छाछ, दही, अंकुरित अनाज, मौसमी फल, सब्जियां और घर का ताजा भोजन हमारे पूर्वजों की स्वस्थ जीवनशैली की पहचान रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आधुनिकता के नाम पर अपनी इस समृद्ध खाद्य संस्कृति को त्यागने के बजाय उसे नए स्वरूप में बच्चों तक पहुंचाएं। यदि विद्यालयों की कैंटीन में स्थानीय और पारंपरिक पौष्टिक व्यंजन उपलब्ध कराए जाएं, तो बच्चे धीरे-धीरे उसी स्वाद के अभ्यस्त हो सकते हैं।

आपको समाज सेवा करने का मौका देता है फार्मासिस्ट करियर

फार्मासिस्ट बनकर आपको समाज की सेवा करने का भी मौका मिलता है। ऐसे में यदि आप भी फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, तो इससे जुड़ी सभी डिटेल्स के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है।

अक्सर छात्र अपने करियर को लेकर काफी परेशान रहते हैं। क्योंकि मेहनत के साथ ही सही कोर्स का चुनाव करना भी जरूरी होता है। ऐसे में आप फार्मासिस्ट बन करने करियर को नई दिशा दे सकते हैं।

फार्मासिस्ट बनकर आपको समाज की सेवा करने का भी मौका मिलता है। ऐसे में यदि आप भी फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, तो इससे जुड़ी सभी डिटेल्स के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इस कोर्स की सारी डिटेल्स बताने जा रहे हैं।

क्वालिफिकेशन

फार्मासिस्ट बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं है। छात्र को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथ्स विषय से 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं के बाद बैचलर ऑफ फॉर्मेसी की डिग्री हासिल करनी होगी। बी फार्मा का कोर्स 4 साल का होता है। वहीं आप चाहें तो मास्टर ऑफ फार्मेसी भी कर सकते हैं, यह दो साल का कोर्स होता है। इसमें पीएचडी का भी एक ऑप्शन होता है, पीएचडी कर आप शोध और शिक्षण के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं।

चयन प्रक्रिया

बी.फार्मा में एडमिशन के लिए अधिकतम राज्यों और विश्वविद्यालयों द्वारा एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कराए जाते हैं। तो वहीं कुछ प्रमुख परीक्षाओं में CUET और राज्य स्तरीय परीक्षाएं आदि भी शामिल हैं। एंट्रेस एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग की जाती है।

झइन जगहों पर कर सकते हैं नौकरी

- अस्पताल और क्लीनिक
- फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री
- रिटेल फार्मेसी
- रेगुलेटरी अफेयर्स
- शिक्षण

सैलरी

फार्मासिस्ट की सैलरी अनुभव, कार्यक्षेत्र और नौकरी की लोकेशन आदि पर निर्भर करती है। बता दें कि एक फार्मासिस्ट की औसत सैलरी 2.5 लाख से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष हो सकती है। एक्सपीरियंस के साथ ही सैलरी बढ़ती जाती है। अनुभवी फार्मासिस्ट की सैलरी 8 लाख से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष या इससे भी ज्यादा हो सकती है।

करियर में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकते हैं एआई शॉर्ट टर्म कोर्स

इन दिनों बहुत सारे लोग नौकरी, बिजनेस या फिर पढ़ाई करते हुए कई दूसरे स्किल भी सीख रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों के पास समय नहीं होता है, वह शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। बता दें कि यह कोर्स पूरी तरह से ऑनलाइन होते हैं।

इन दिनों बहुत सारे लोग नौकरी, बिजनेस या फिर पढ़ाई करते हुए कई दूसरे स्किल भी सीख रहे हैं। लेकिन रेग्यूलर कोर्स करने के लिए आपको किसी संस्थान में जाना होता है, इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। ऐसे में जिन लोगों के पास समय नहीं होता है, वह शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। बता दें कि यह कोर्स पूरी तरह से ऑनलाइन होते हैं। वहीं इनमें से बहुत सारे कोर्स ऐसे भी होते हैं, जिनको करने के लिए आप किसी खास या तय समय पर कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना पड़ता, बल्कि आप अपने समयानुसार इन कोर्स को कर सकते हैं।

राज्य और केंद्र सरकार के अलावा Google, IBM, Reuters जैसी कंपनियां भी इन कोर्सेज को कराती हैं। इन कोर्स की फीस 500 रुपए से लेकर 15 हजार रुपए तक हो सकती है। इनमें से कुछ कोर्स फ्री होते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट लेने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं।

AI कोर्स

आपको बता दें कि गूगल समेत कई कंपनियों की तरफ से कई तरह के AI कोर्स जारी किए गए हैं। यह कोर्स ऑनलाइन और पूरी तरह फ्री हैं। करियर में आगे बढ़ने के लिए यह कोर्स आपकी मदद कर सकते हैं। हालांकि यह कोर्स अंग्रेजी में होते हैं और आपको थोड़ी-बहुत कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। बाकि इन कोर्स को करने के लिए किसी खास तरह की योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में आप यह कोर्स को अपनी रेज्यूमे में जोड़कर अच्छी नौकरी की तलाश पूरी कर सकते हैं।

लार्ज लैग्वेज मॉडल्स

इस कोर्स को करने के बाद आप भी ChatGPT जैसा प्लैटफॉर्म बना सकते है। इस कोर्स में आपको यह सिखाया जाता है कि किस तरह से ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म पर इमेज और कंटेंट क्रिएट किया जाता है। आप इस कोर्स को करने के बाद किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल बना सकते हैं। यह किसी भी कंटेंट को दूसरी भाषा में ट्रांसफर कर सकते हैं। मिनटों में लंबे असाइनमेंट या प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। लार्ज लैग्वेज मॉडल्स कोर्स में यह भी बताया व सिखाया जाता है कि आप किस तरह प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग की मदद से आउटपुट पर कंट्रोल पा सकते हैं। इस कोर्स की अवधि 8 घंटे की है।

इमेज जनरेटर

इमेज जनरेटर का कोर्स कर आप AI की मदद से कैसा भी कोई भी फोटो जनरेट कर सकते हैं। इस कोर्स में आप यह भी सीख सकते हैं कि कम रिजॉल्यूशन वाली फोटो को हाई रिजॉल्यूशन में कैसे बदलें। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी का चेहरा भी डिजाइन कर सकते हैं और लैंडस्केप इमेज भी तैयार कर सकती हैं। इस कोर्स में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के आधार पर इमेज, स्केच और कार्टून आदि बनाने की ट्रेनिंग दी भी जाती है। इस कोर्स की अवधि 8 घंटे की है।

6 महीने का समय

इन कोर्स को करने का समय 3 घंटे से लेकर 6 महीने तक का हो सकता है। कोर्स को कब करना है, कितने बजे से कितने बजे तक करना है, यह फिक्स नहीं होता है। अपनी सुविधानुसार आप किसी भी समय इस कोर्स को कर सकते हैं।

AI में कैसे जॉब पाएं?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से तकनीक क्षेत्र लेकर मीडिया लाइन में इसका काफी प्रयोग हो रहा है। यह आज के समय में काफी डिमांड में है। AI क्षेत्र में नौकरियां भी काफी तेजी से बढ़ रही हैं। AI को करियर के रुप में देखा जा रहा है। बड़ी-बड़ी कंपनियां AI पर फोकस कर रही हैं, इसी तरह लोग भी AI बेस्ड नई नौकरी पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि, AI में कई नौकरियां शामिल हैं जैसे मशीन लर्निंग इंजीनियर, प्रॉम्पट इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट या AI रिचर्स इत्यादि। अगर आप इसे करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बता दें किस तरह की पढ़ाई करनी है और कंपनियां को किस तरह की प्रोफाइल वाले रिज्यूम पसंद आते हैं।

टेक्निकल पढ़ाई

दरअसल, बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ रिक्रूटर्स का कहना है कि AI जॉब के लिए टेक्निकल एजुकेशन होना काफी जरुरी है। उनका मानना है कि अक्सर AI बेस्ड जॉब देने वाली कंपनियां कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, मैथ्स और एप्लाइड साइंस को कुछ मेन डिग्री के रुप में देखते हैं।

कानून की समझ हो

टैलेंट फर्म कैरेक्स कंसल्टिंग ग्रुप के एक टेक्निकल रिक्रूटर एंड्री मेंडोजा ने कहा कि क्योंकि AI एक नया फील्ड है, इसलिए इसकी ट्रेनिंग एक अच्छा ऑप्शन है। आगे उन्होंने बताया कि कानून की गहरी समझ होना जरुरी है और बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस भी होनी जरुरी है। लेकिन शुरुआत में इतना काफी नहीं है। अगर आप इस नई फील्ड में अपनी जगह बनाने चाहते हैं तो आपका टेक्निकल बैकग्राउंड से होना बहुत जरुरी है। जो लोग अलग-अलग पढ़ाई या करियर वाले स्कूल से आत हैं, उन्हें AI में नौकरी नहीं मिल सकती है।

प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए

अगर आप AI में नौकरी पाना चाहते हैं तो AI की स्पेफिक टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी और इंजीनियर होना बहुत जरुरी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना भी जरुरी है। AI में नौकरियों के लिए आवेदकों के लिए पायथन या जावास्क्रिप्ट की समझ होनी चाहिए।

कोडिंग की समझ भी जरुरी

एक्सपर्ट के मुताबिक, कोडिंग सर्टिफिकेट्स नौकरी पाने की संभावनाएं बढ़ा देते हैं। अगर AI में बेहतरीन नौकरी चाहिए तो कोडिंग की अच्छी समझ होनी चाहिए।

बिना कोडिंग के भी मिलेगा करोड़ों का इंटरनेशनल पैकेज, बढ़ रही इस बीटेक ब्रांच की डिमांड

आजकल जब भी कोई इंजीनियरिंग करने की सोचता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में बीटेक यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का नाम आता है. सबको लगता है कि बड़ा पैकेज और शानदार करियर सिर्फ कोडिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही मिल सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी फील्ड है जहां बिना कोडिंग के भी छात्रों को करोड़ों रुपये के इंटरनेशनल पैकेज मिल रहे हैं. वो है बीटेक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग

अगर आपकी रुचि कोर इंजीनियरिंग में है और आप दुनिया घूमने के साथ-साथ एक शानदार सैलरी पैकेज चाहते हैं, तो यह फील्ड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. आइए जानते हैं कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग क्या है और क्यों यह आज के समय में इतनी डिमांड में है.

क्या होती है बीटेक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग

पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जो जमीन के नीचे से कच्चे तेल और नेचुरल गैस को सुरक्षित और सही तरीके से बाहर निकालने की टेक्नीक पर काम करती है. एक पेट्रोलियम इंजीनियर का काम सिर्फ खुदाई करना नहीं होता. वे यह पता लगाते हैं कि जमीन या समुद्र के नीचे तेल कहां है, उसे बाहर निकालने के लिए कौन सी मशीनें लगेंगी और कैसे कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा तेल निकाला जा सकता है.

क्यों मिल रहे हैं इसमें इंटरनेशनल पैकेज

बहुत से लोगों को लगता है कि दुनिया अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, तो तेल की डिमांड कम हो जाएगी. लेकिन सच यह है कि प्लास्टिक, दवाइयां, केमिकल और भारी उद्योगों में आज भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कोई दूसरा विकल्प नहीं है. आजकल ज्यादातर छात्र कंप्यूटर साइंस की तरफ भाग रहे हैं, इसलिए बीटेक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के फील्ड में टैलेंटेड प्रोफेशनल्स की भारी कमी हो गई है. डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियां जैसे अरामको, शेल, और शेवरॉन भारतीय छात्रों को सीधे कॉलेज कैंपस से ही करोड़ों रुपये के इंटरनेशनल पैकेज पर हायर कर रही हैं.

मिडिल ईस्ट में नौकरियों की भरमार

पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ बिजनेस है. इस कोर्स को करने के बाद आपको सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में काम करने का मौका मिलता है. विशेष रूप से दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान जैसे मिडिल ईस्ट (खाड़ी) देशों में तेल के विशाल भंडार हैं. इसके अलावा अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी पेट्रोलियम इंजीनियर्स की भारी मांग रहती है. इन देशों में काम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वहां सैलरी बहुत ज्यादा होती है और कई देशों में तो इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता है.

कोर्स के दौरान क्या-क्या पढ़ना होता है

अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आपको 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ना जरूरी है. इसके बाद आप IITs या देश की अन्य टॉप यूनिवर्सिटीज से 4 साल का बीटेक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं. इस कोर्स के दौरान आपको नीचे दिए गए मुख्य विषयों के बारे में सिखाया जाता है:

ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी: जमीन और समुद्र में गहरे कुएं कैसे खोदे जाते हैं.

रिजर्वोइयर इंजीनियरिंग: तेल के भंडारों का सही अंदाजा लगाना.

प्रोडक्शन ऑपरेशन्स: तेल को जमीन से बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया.

जियोलॉजी: धरती की परतों और चट्टानों का अध्ययन करना.

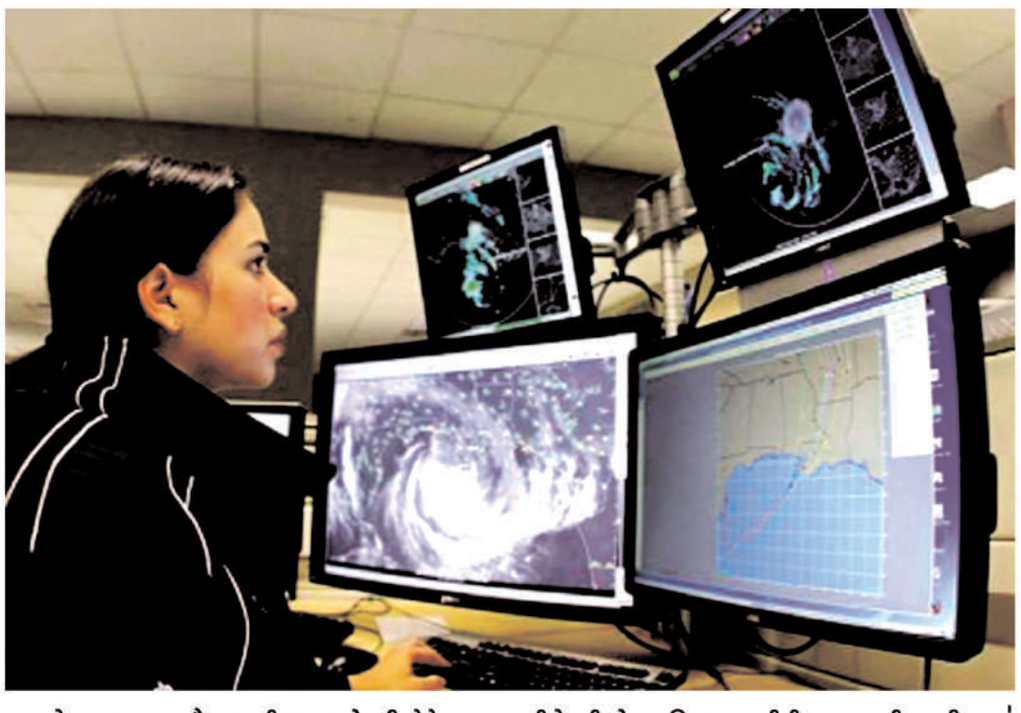

हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी

आपके शहर, घर और पसंदीदा जगहों की सेटेलाइट तस्वीरों की हो या फिर उस जीपीएस तकनीक की, जिसकी मदद से आप कोई पता तलाशते हैं, किसी अनजाने क्षेत्र में जाने के लिए आसान रास्ता ढूंढ़ते हैं या कोई नजदीकी होटल खोजते हैं। कुछ साल पहले तक कोरी कल्पना लगने वाली ये तकनीकें अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। यह सब संभव हुआ है जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी के कारण।

जीआईएस या जियोमेटिक्स एक नई वैज्ञानिक अवधारणा है, जिसका इस्तेमाल जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस या जियोस्पेशल इंफॉर्मेशन स्टडीज में होता है। अकादमिक रूप से यह जियोइंफॉर्मेटिक्स विषय की एक शाखा है। इस विषय के सिद्धांतों को आधार बनाकर तैयार की गई तकनीकों को जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस तकनीक की मदद से सभी तरह की भौगोलिक सूचनाओं को इकट्ठा करके उनका संग्रहण, विश्लेषण और प्रबंधन किया जा सकता है। इस कार्य में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस), ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जाता है। भारत में जियोमेटिक्स का क्षेत्र अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन एक उद्योग के रूप में यह तेजी से विस्तार कर रहा है। इसको अपने कामकाज के लिए बड़े पैमाने पर स्पेशल डाटा (आकाशीय आंकड़ों) की जरूरत होती है। मगर शुरुआती दौर में होने की वजह से इस उद्योग में कुशल पेशेवरों की कमी बनी हुई है। इस कारण यहां रोजगार और तरक्की की दृष्टि से काफी संभावनाएं हैं। इस तकनीक का लाभ परिवहन, रक्षा, विनिर्माण और संचार सहित सैकड़ों क्षेत्रों में लिया जा रहा है। अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज मैनेजमेंट, इन-कार नेविगेशन सिस्टम, वचरुअल ग्लोब, पब्लिक हेल्थ, इंवायरन्मेंटल मॉडलिंग एंड एनालिसिस, मिलिट्री, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, मीटिअरोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड एटमॉस्फेयर मॉडलिंग, बिजनेस लोकेशन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन, टेलीकम्यूनिकेशंस, क्रिमिनोलॉजी एंड क्राइम सिमुलेशन, एविएशन और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट आदि से संबंधित कार्यों में जियोइंफॉर्मेटिक्स काफी मददगार साबित हो रहा है। क्लाइमेट चेंज स्टडीज, टेलीकम्यूनिकेशंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और उसकी तैयारियों में इस तकनीक से विशेष मदद मिलती है। इसी तरह बिजनेस लोकेशन प्लानिंग, आर्किटेक्चर और आर्कियोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन में इस तकनीक को अपनाए जाने के बाद काम की गुणवत्ता में काफी सुधार आया है। जियोग्राफी और अर्थ साइंस के विशेषज्ञों और शोधार्थियों को भी इस तकनीक से सटीक अध्ययन में काफी मदद मिली है।

जियोइंफॉर्मेटिक्स के बढ़ते महत्व का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब यह सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों में बड़े निर्णयों का आधार भी बनने लगा है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान, पर्यावरण एजेंसियां, सरकार, शोध-शिक्षण संस्थान, सर्वेक्षण और मानचित्रीकरण संगठन अपने कामकाजी फैसलों में इस तकनीक से प्राप्त आकंड़ों को वरीयता देते हैं। कई सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों ने अपने दैनिक कार्यों का प्रबंधन करने के लिए भी स्पेशल डाटा का उपयोग शुरू कर दिया है।

संभावनाएं

जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी में कई तरह के रोजगार उपलब्ध हैं। साथ ही नए-नए अवसर भी इस क्षेत्र में पैदा हो रहे हैं। एनालिस्ट, काटरेग्राफर, सर्वेयर, प्लानर, एरियल फोटोग्राफर और मैपिंग टेक्निशियन आदि रोजगार के कुछ प्रमुख विकल्प हैं, जिन्हें जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे छात्र चुन सकते हैं।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान एवं स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां सर्वोच्च प्राथमिकता से करें : कलेक्टर

समय-सीमा बैठक में दिए निर्देश, हर घर तिरंगा अभियान, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सुशासन से जुड़े विषयों की हुई विस्तृत समीक्षा

सीधी। कलेक्टर विकास मिश्रा ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी विभागों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के माध्यम से प्रशासन सीधे जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। इसलिए सभी अधिकारी पूरी तैयारी, समन्वय और संवेदनशीलता के साथ अभियान का संचालन सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले जनसंवाद एवं समाधान शिविरों में प्राप्त प्रत्येक शिकायत एवं आवेदन का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। भ्रमण के दौरान शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों तथा विभागीय संस्थाओं का प्रभावी निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों, राजस्व संबंधी मामलों, फार्मर आईडी, आयुष्मान कार्ड, समग्र ई-केवाईसी तथा अन्य जनहित के कार्यों को अभियान के दौरान सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को सौंपे गए दायित्वों का समयबद्ध निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समारोह से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं पूर्व निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कर ली जाएं, ताकि राष्ट्रीय पर्व का आयोजन गरिमा, अनुशासन एवं भव्यता के साथ संपन्न हो। कलेक्टर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची 10 अगस्त तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक जिलेभर में अभियान का व्यापक एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय के

साथ जनप्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थानों, स्व-सहायता समूहों, स्वयंसेवी संगठनों एवं आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि 10 अगस्त को जिला मुख्यालय में 'हर घर तिरंगा' अभियान के अंतर्गत भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाए तथा अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित कर राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जाए।

वर्षा ऋतु को देखते हुए कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य विभाग एवं नगरीय निकायों को शुद्ध पेयजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल स्रोतों की नियमित जांच, क्लोरीनेशन एवं जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सतत निगरानी रखने तथा आवश्यक जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना की नियमित निगरानी की जाए। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए तथा निर्धारित मीनू का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

बैठक में चिरैया अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा शिक्षा विभाग को समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बालिका छात्रावासों एवं विद्यालयों में किशोरियों को स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया से बचाव, मासिक धर्म स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति व्यापक रूप से जागरूक किया जाए, ताकि किशोरियों के स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार सुनिश्चित हो सके।

कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को ई-अटेंडेंस एवं ई-ऑफिस प्रणाली का प्रभावी एवं शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं कार्यकुशलता बढ़ेगी। किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले में चयनित विद्यार्थियों के लिए संचालित की जा रही नीट एवं आईआईटी-जेईई कोचिंग शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन, अध्ययन सामग्री एवं विशेषज्ञ शिक्षकों की सुविधा समय पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।

बैठक में अन्य समय-सीमा वाले प्रकरणों की भी विभागवार समीक्षा की गई तथा लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी मैदानी स्तर पर नियमित भ्रमण कर शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की सतत निगरानी करें तथा नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 और स्वतंत्रता दिवस से जुड़े सभी कार्यक्रम शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं, इसलिए इनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, अपर कलेक्टर बीपी पाण्डेय, उपखंड अधिकारी मझौली संजीव पाण्डेय, गोपद बनास प्रिया पाठक, चुरहट अजय शर्मा, सिहावल राकेश शुक्ला, कुसमी सागर जैन सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

उद्योगों के विकास और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड एवं निर्यात संवर्धन बोर्ड की बैठक आयोजित

सीधी। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के अंतर्गत प्रस्तावित उद्योग संवाद की तैयारियों को लेकर सोमवार को कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड एवं जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन बोर्ड की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के उद्यमियों एवं भावी उद्यमियों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक सुझाव प्राप्त किए गए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित उद्योग संवाद का उद्देश्य जिले के उद्यमियों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, सुझावों एवं अपेक्षाओं को समझना तथा उनके त्वरित निराकरण के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योगों की स्थापना एवं संचालन में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा निवेश और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएं। बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के विकास, नए उद्योगों की स्थापना, स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, निर्यात की संभावनाओं तथा उद्यमियों को उपलब्ध कराई जा रही शासकीय सुविधाओं पर चर्चा की गई। साथ ही जिला स्तर पर उद्योगों के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं उनके समाधान के संबंध में उद्यमियों से सुझाव प्राप्त किए गए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक प्रत्येक माह नियमित रूप से उनकी अध्यक्षता में आयोजित की जाए, ताकि उद्योगों से संबंधित समस्याओं का समयबद्ध निराकरण हो सके तथा निवेशकों एवं उद्यमियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। बैठक में लीड बैंक मैनेजर (एलडीएम) अवध बिहारी चौधरी, उप संचालक कृषि आरएस गुप्ता, उप संचालक पशुपालन डॉ राजेश सोनी, जिला खनिज अधिकारी कपिलमुनी शुक्ला, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) मनीष त्रिपाठी, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (डीआईसी) अभिलाष मरावी, लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष, जिला व्यापारी संघ के अध्यक्ष सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं उद्यमी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस एवं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जयंती पर विविध कार्यक्रम आयोजित

सीधी। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के अंतर्गत राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस एवं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जयंती के अवसर पर विविध शैक्षणिक एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत की वैज्ञानिक परंपरा से जोड़ते हुए आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के विज्ञान, अनुसंधान एवं स्वदेशी उद्योग के क्षेत्र में दिए गए अमूल्य योगदान से परिचित कराना था।

इस अवसर पर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवन एवं कृतित्व पर व्याख्यान, उनके वैज्ञानिक योगदान पर परिचर्चा, विज्ञान मॉडल एवं प्रोजेक्ट प्रदर्शनी तथा विद्यार्थियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार और शोध के प्रति रुचि विकसित करने का प्रयास किया गया।

इसी क्रम में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) द्वारा रैंक सेरेमनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को उच्च रैंक प्रदान कर सम्मानित किया गया।

महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रभाकर सिंह ने विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा, वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान की भावना को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जीवन समर्पण, स्वदेशी भावना और वैज्ञानिक उत्कृष्टता का प्रेरणास्रोत है।

कार्यक्रम के संयोजक डॉ. उमेश कुमार विश्वकर्मा ने आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवन, शोध कार्यों तथा भारतीय रसायन विज्ञान के विकास में उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों में सहभागिता करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में डॉ. अरविंद कुमार त्रिपाठी, डॉ. आई.पी. प्रजापति, डॉ. अरुणा ठाकुर, डॉ. राममिलन प्रजापति, डॉ. विनोद प्रजापति, डॉ. गंगा बैरागी, डॉ. दिलीप सोनी, डॉ. राकेश सिंह चौहान, डॉ. दिवाकर सिंह, डॉ. उमाकांत साहू तथा डॉ. नुसरत अली सहित महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

विकासखंड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक पदों के लिए 5 अगस्त को होगी काउंसलिंग

सीधी। जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र सीधी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के विकासखंडों में विकासखंड अकादमिक समन्वयक (बीएसी) तथा जनशिक्षा केन्द्रों में जनशिक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए 5 अगस्त 2026 को काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग से प्राप्त माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक संवर्ग की वरिष्ठता सूची के आधार पर ऐसे पात्र लोक सेवकों की सूची जारी की गई है, जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 की स्थिति में 52 वर्ष से कम है। इन पात्र शिक्षकों को विकासखंड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक के पदों पर कार्य करने की सहमति प्राप्त करने हेतु काउंसलिंग में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। काउंसलिंग 5 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), सीधी में आयोजित होगी।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026, 7 अगस्त से जिलेभर में लगेंगे जन-संवाद एवं समाधान शिविर

कलेक्टर ने नियुक्त किए जिला एवं सेक्टर स्तरीय नोडल अधिकारी, गांवों से लेकर नगरीय वार्डों तक पहुंचेगा प्रशासन

सीधी। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, आमजन की शिकायतों का मौके पर त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने तथा प्रशासन और नागरिकों के बीच विश्वास को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के अंतर्गत जिलेभर में 7 अगस्त से जन-संवाद एवं समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के सफल संचालन के लिए कलेक्टर विकास मिश्रा ने जिला एवं उपखंड स्तर पर नोडल अधिकारियों एवं सेक्टर प्रभारियों की नियुक्ति करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित इस अभियान के तहत क्षेत्र भ्रमण, विभागीय संस्थाओं का निरीक्षण, जन-संवाद, उद्यम संवाद तथा शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। साथ ही लोक सेवाओं का समयबद्ध प्रदाय सुनिश्चित करते हुए आमजन की समस्याओं का यथासंभव मौके पर ही निराकरण किया जाएगा।

आदेशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी को अभियान का जिला नोडल अधिकारी तथा राजस्व संबंधी सेवाओं के लिए बी.पी. पाण्डेय, अपर कलेक्टर को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपखंड स्तर पर संबंधित एसडीएम कार्यक्रम के नोडल अधिकारी होंगे, जबकि संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगर निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी के रूप में दायित्व निभाएंगे। जिला स्तर पर स्थापित कॉल सेंटर के लिए स्वर्णा दीवान, डिप्टी कलेक्टर को नोडल अधिकारी तथा जिला प्रबंधक लोक सेवा एवं जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। तकनीकी सहयोग हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को तकनीकी नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कुसमी विकासखंड के भुइमाड़ में केशलार, कैरल, गैवटा, सोनगढ़, अमरोला एवं भुइमाड़ ग्रामों, मझौली के चमराडोल में चमराडोल, नौढ़िया, परसिली, बोदारीटोला एवं करमाई ग्राम पंचायतों, रामपुर नैकिन के पटना में पटना, मझिगवां, पिपराव एवं बुढ़गौना ग्राम पंचायतों, सिहावल के बघोर में बघोर, मेढ़ौली, गेरूआ एवं दुधमनियां ग्राम पंचायतों तथा सीधी के धुम्मा में मवई, टीकट कला, टीकट खुर्द, बघऊ एवं चिलरीकला ग्राम पंचायतों के नागरिकों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

वहीं नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद चुरहट के वार्ड क्रमांक 11 से 15, नगर परिषद मझौली के वार्ड क्रमांक 11 से 15, नगर परिषद रामपुर नैकिन के वार्ड क्रमांक 11 से 15 तथा नगर पालिका परिषद सीधी के वार्ड क्रमांक 21 से 24 के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक शिविर के लिए अलग-अलग जिला स्तरीय नोडल अधिकारी एवं सेक्टर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो संपूर्ण व्यवस्था की निगरानी करेंगे।

शिविरों का आयोजन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान अधिकारी विभागीय संस्थाओं का निरीक्षण करेंगे, जन-संवाद एवं उद्यम संवाद में शामिल होंगे तथा प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद सायं 6 बजे सेक्टर मुख्यालय पर समीक्षा बैठक आयोजित होगी। सेक्टर प्रभारी प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट संबंधित एसडीएम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उपलब्ध कराएंगे, जिसे रात्रि 8 बजे तक कॉल सेंटर मुख्यालय भेजा जाएगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए तथा संबंधित क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम की सूचना उपलब्ध कराई जाए।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में सीधी का शानदार प्रदर्शन

देशभर में हासिल किया दूसरा स्थान

सीधी। कलेक्टर विकास मिश्रा के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के आउटकम बेस्ड इंडिकेटर्स में सीधी जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 98.17 कम्पोजिट स्कोर प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के साथ सीधी ने देशभर में दूसरा स्थान हासिल कर प्रदेश और जिले का गौरव बढ़ाया है।

यह रैंकिंग उन जिलों को प्रदान की जाती है, जहां कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से वास्तविक और सकारात्मक बदलाव दिखाई देते हैं। सीधी जिले में पिछले वर्ष की तुलना में फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, दलहन एवं तिलहन की खेती के रकबे का विस्तार, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा तथा फसल विविधीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, श्री अन्न (मिलेट्स) के उत्पादन में वृद्धि तथा किसानों तक शासकीय योजनाओं का प्रभावी लाभ पहुंचाने के प्रयासों ने जिले को यह उपलब्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जिले की इस सफलता के पीछे जिला प्रशासन, कृषि एवं संबद्ध विभागों के समन्वित प्रयास, योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग तथा किसानों की सक्रिय भागीदारी रही है। कृषि क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के कारण सीधी जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

अब योजना के अगले चरण में कृषि अधोसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026, जनसंवाद, निरीक्षण और त्वरित समाधान पर रहेगा विशेष फोकस

7 अगस्त से 8 जनवरी तक चलेगा अभियान, प्रत्येक शुक्रवार गांवों और नगरीय वार्डों में पहुंचेंगे अधिकारी

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने मीडिया को दी अभियान की विस्तृत जानकारी

सीधी। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के प्रभावी संचालन एवं व्यापक जनजागरूकता के उद्देश्य से सोमवार को जिला पंचायत सभागार में आयोजित मीडिया संवाद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने अभियान की विस्तृत रूपरेखा, उद्देश्य एवं कार्ययोजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश शासन द्वारा 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक संचालित किए जाने वाले इस अभियान का उद्देश्य शासन और जनता के बीच विश्वास को और अधिक मजबूत करना, लोक सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण करना है। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्रत्येक शुक्रवार जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारी निर्धारित ग्राम पंचायतों एवं नगरीय वार्डों का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान जनसंवाद आयोजित कर नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे, लंबित प्रकरणों का मौके पर निराकरण करेंगे तथा आवश्यकतानुसार नए आवेदन भी प्राप्त किए जाएंगे। प्रत्येक भ्रमण दिवस के अंत में समीक्षा बैठक आयोजित कर अभियान की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के शत-प्रतिशत निराकरण पर विशेष जोर रहेगा। इसके साथ ही अविवादित

नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारा, न्यायालयीन आदेशों का राजस्व अभिलेखों में अमल, समग्र आईडी की ई-केवाईसी, आधार कार्ड निर्माण एवं अद्यतन, पात्र किसानों की फार्मर आईडी तथा पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निर्माण जैसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान जिले में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा, जिनके माध्यम से आम नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक परामर्श एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण कर चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाओं, चिकित्सा उपकरणों तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने की स्थिति, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल एवं निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं की प्रगति, आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के वजन एवं ऊंचाई मापन, कुपोषण मुक्ति गतिविधियों तथा पोषण सेवाओं की समीक्षा भी की जाएगी। स्कूलों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति, अध्ययन की गुणवत्ता और मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही खाद-बीज एवं कृषि आदानों की उपलब्धता, उचित मूल्य दुकानों की कार्यप्रणाली तथा आम नागरिकों से फीडबैक प्राप्त किया जाएगा। सड़क, तालाब, अमृत सरोवर, बांध, जल जीवन मिशन की संरचनाएं, शासकीय भवन, खेत एवं फसलों सहित विभिन्न विकास कार्यों और परिसंपत्तियों का भी स्थल निरीक्षण किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि आईटीआई, मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक सहकारी समितियां, तहसील कार्यालय, कृषि उपज मंडी, पुलिस थाना, लोक सेवा केन्द्र, छात्रावास, आश्रम एवं औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा खाद-बीज विक्रेताओं, गैस एजेंसियों, पेट्रोल पंपों, विस्फोटक एवं पटाखा लाइसेंसधारियों, शस्त्र विक्रेताओं तथा निजी विद्यालयों का भी आवश्यकतानुसार निरीक्षण किया जाएगा। क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, संबल योजना एवं अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी।

रकुल प्रीत सिंह ने शेयर किया पति जैकी भगनानी के साथ काम करने का अनुभव

आधा समय काम और खाने की चर्चा में बीतता है

अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और निर्माता-अभिनेता जैकी भगनानी की जोड़ी ने अपने रिश्ते को हमेशा निजी रखा है, लेकिन समय-समय पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी जिंदगी से जुड़ी खूबसूरत झलकियां भी साझा करते रहते हैं। हाल ही में रकुल ने जैकी के साथ अपने काम और निजी रिश्ते को लेकर एक खास बात साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि पति के साथ काम करना उनके लिए कितना खास और मजेदार अनुभव है। रकुल प्रीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर जैकी भगनानी के साथ कुछ तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों में दोनों के बीच की खास बॉन्डिंग नजर आ रही है। पोस्ट में रकुल ने फैंस द्वारा पूछे जाने वाले उस सवाल का जवाब दिया कि पति के साथ काम करना कैसा होता है।

रकुल ने अपने कैप्शन में लिखा, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि साथ काम करने का अनुभव कैसा है, तो इसका जवाब बहुत आसान है। हम दोनों का आधा समय काम को लेकर बातचीत करने में और बाकी समय हंसी-मजाक करने और खाने की चर्चा करने में बीतता है। मुझे यह अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी सोच और तालमेल एक जैसी है। जब दो लोग किसी काम को लेकर एक जैसी एनर्जी और उत्साह रखते हैं तो साथ मिलकर कुछ नया बनाना और भी खास हो जाता है।

अभिनेत्री ने आगे लिखा, साथ मिलकर जिंदगी बनाना अपने आप में एक अलग अनुभव है, लेकिन जब आप दोनों मिलकर ऐसी चीज बनाने की कोशिश करते हैं, जिसे लेकर दोनों उत्साहित हों, तो वह सफर और भी खास बन जाता है।

रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने साल 2021 में अपने रिश्ते का खुलासा किया था। इसके बाद दोनों ने 2024 में गोवा में शादी की थी। उनकी शादी में परिवार के करीबी लोग और खास दोस्त शामिल हुए थे। शादी के बाद भी दोनों अपने-अपने काम में सक्रिय हैं और अक्सर एक-दूसरे को सहयोग करते नजर आते हैं।

मॉडलिंग क्या होती है, ये भी नहीं जानती थीं तनुश्री चक्रवर्ती, फिर बनीं बंगाली सिनेमा की पहचान

फिल्मों की दुनिया में कई सितारों का सफर किसी प्लानिंग के तहत शुरू नहीं होता। कुछ लोग अचानक मिले मौके को अपनी मेहनत से बड़ी पहचान में बदल देते हैं। बंगाली सिनेमा की अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज वह अपनी खूबसूरती, अभिनय और अलग अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि जब उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था, तब उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। एक मामूली शुरुआत से तनुश्री ने धीरे-धीरे विज्ञापनों, फिल्मों और फिर राजनीति तक का सफर तय किया। तनुश्री चक्रवर्ती का जन्म 6 अगस्त 1984 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से की। इसके बाद उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से जुड़े बसंती देवी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, लेकिन शुरुआत में उन्हें नहीं पता था कि मॉडलिंग क्या होती है। तनुश्री ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने मॉडलिंग शुरू की, तब उन्हें नहीं पता था कि मॉडलिंग में काम कैसे होता है और इस क्षेत्र की असली दुनिया कैसी है। धीरे-धीरे उन्होंने इस काम को समझा और कई विज्ञापनों में नजर आने लगीं। उनका एक बांग्लादेशी मसाला ब्रांड का विज्ञापन काफी लोकप्रिय हुआ, जिसने उन्हें अलग पहचान दिलाई। यही छोटा सा कदम आगे चलकर उनके फिल्मी करियर की शुरुआत बना। मॉडलिंग के बाद तनुश्री ने बंगाली फिल्मों में कदम रखा। साल 2010 में फिल्म बोंधु एसो तुमी से उन्होंने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद साल 2011 में आई फिल्म उरो चिट्ठी ने उन्हें दर्शकों के बीच पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बंगाली सिनेमा की कई चर्चित फिल्मों में काम किया। साल 2012 में आई बेडरूम उनके करियर की अहम फिल्मों में से एक रही। इसके बाद उन्होंने ओबिशोप्टो नाइटी, विंडो कनेक्शन्स, बुनो हांश और खाद जैसी फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए। उनकी एक्टिंग को दर्शकों और फिल्म समीक्षकों ने काफी पसंद किया। उन्होंने सिर्फ ग्लैमरस भूमिकाएं ही नहीं कीं, बल्कि अलग तरह के किरदारों के जरिए अपनी अभिनय क्षमता भी दिखाई। तनुश्री चक्रवर्ती ने फिल्मों के साथ-साथ टीवी की दुनिया में भी काम किया। वह जी बांग्ला के लोकप्रिय शो दीदी नंबर. 1 में नजर आईं और बाद में कई टीवी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनीं। उन्होंने ब्यूटी और लाइफस्टाइल शो संपूर्ण की होस्टिंग भी की।

वर्ल्डवाइड भी छप्परफाड़ कमाई जारी, जानें बाकी फिल्मों का हाल

300 करोड़ पार स्पाइडर-मैन- ब्रांड न्यू डे

टॉम हॉलैंड स्टारर हॉलीवुड फिल्म स्पाइडर-मैन- ब्रांड न्यू डे वीकेंड पर ही नहीं वीकडेज पर भी जमकर कमाई कर रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस के अलावा वर्ल्डवाइड भी यह जमकर नोट छाप रही है। इस फिल्म ने मंगलवार को भी बढ़िया कमाई की है। इसके अलावा 'द ओडिसी' और 'जन नायकन' का सिनेमाघरों में क्या हाल है, जानिए।

सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म स्पाइडर-मैन- ब्रांड न्यू डे ने छठे दिन यानी मंगलवार को 21.50 करोड़ रुपये कमाए हैं। जबकि पांचवें दिन 23.80 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म का कुल कलेक्शन भी अब तक 303.50 करोड़ रुपये हो चुका है। इस फिल्म में टॉम हॉलैंड एक बार फिर से स्पाइडर मैन के रोल में नजर आए हैं। इस फिल्म के निर्देशक डेस्टिन डेनियल क्रेटन हैं।

'स्पाइडर-मैन- ब्रांड न्यू डे' कमाई के मामले में वर्ल्डवाइड भी हैरान कर रही है। मंगलवार सुबह तक इस फिल्म ने 1.052 बिलियन डॉलर की कमाई की थी। इसने नॉर्थ अमेरिका में 407 मिलियन डॉलर का कलेक्शन शामिल है। चीन में इस फिल्म ने 132.9 मिलियन डॉलर कमाए हैं। वहीं यूके में 55.6 मिलियन डॉलर और मेक्सिको में 43.6 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया है।

दुनिया भर के कई देशों में यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। जैसे फ्रांस में इस फिल्म ने 31.4 मिलियन डॉलर, साउथ कोरिया में 28 मिलियन डॉलर, ब्राजील में 27.7 मिलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया में 23.4 मिलियन डॉलर, जर्मनी में 22.5 मिलियन डॉलर और इटली में 20.7 मिलियन डॉलर की कमाई हुई है।

'स्पाइडर-मैन- ब्रांड न्यू डे' हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंडगेम के बाद अमेरिका में ओपनिंग वीकेंड पर 300 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाने वाली दूसरी फिल्म बन गई है।

फिल्म 'जन नायकन' ने रिलीज के 13वें दिन 2.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। जबकि 12वें दिन 3.85 करोड़ रुपये की कमाई की है। फिल्म की कुल कमाई भी अब तक 181.57 करोड़ रुपये हो चुकी है। यह फिल्म भी 200 करोड़ रुपये के कलेक्शन के करीब पहुंच चुकी है।

सोहा अली खान ने शेयर की पूरे हफ्ते की खास बातें, डाइजेस्टिव टी से लेकर पुल-अप तक का बताया अनुभव

बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस, किताबों और लाइफस्टाइल से जुड़ी अपडेट देती रहती हैं। इस बार उन्होंने अपने फैंस को बताया कि इस हफ्ते उन्हें कौन-कौन सी चीजें सबसे ज्यादा पसंद आईं। सोहा ने अपनी रोजमर्रा की आदतों, पढ़ने की पसंद और फिटनेस से जुड़ी चीजों के बारे में बात की। सोहा अली खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी इस हफ्ते की तीन पसंदीदा चीजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'मैं रात के खाने के बाद एक खास डाइजेस्टिव टी पीती हूं, जो मेरी शाम की दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। यह चाय पेट को हल्का रखने में मदद करती है। अभिनेत्री ने बताया, यह डाइजेस्टिव टी घर पर आसानी से तैयार की जा सकती है। इसमें दालचीनी, अदरक, तुलसी और सौंफ जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। यह पेय मुझे काफी सुकून देता है, और अब यह मेरी छोटी सी शाम की आदत बन चुकी है। हालांकि, यह चाय हर किसी के लिए सही नहीं हो सकती। खासकर गर्भवती महिलाओं, ब्लड थिनर लेने वाले लोगों, एसिडिटी या रिफ्लक्स की समस्या से जूझ रहे लोगों और डायबिटीज की दवा लेने वालों को इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

डीडीएलजे की सिमरन जैसी नहीं थी काजोल की असली लव स्टोरी, खुद बताई रिश्ते की कहानी

बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल का नाम आते ही सबसे पहले फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (डीडीएलजे) की सिमरन याद आती है, जो प्यार के लिए परिवार और समाज के बीच अपनी जगह बनाती है। पर्दे पर उनकी यह प्रेम कहानी जितनी खूबसूरत दिखी, असल जिंदगी में काजोल की लव स्टोरी उतनी ही अलग थी। खुद काजोल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी और अजय देवगन की कहानी कहीं से भी फिल्मी रोमांस जैसी नहीं थी, बल्कि दोस्ती और समझ के साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ी। आज काजोल अपने अभिनय, बेबाक अंदाज और शानदार करियर के लिए जानी जाती हैं। काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई में हुआ था। वह एक ऐसे परिवार से आती हैं, जिसका रिश्ता फिल्म इंडस्ट्री से रहा है। उनकी मां तनुजा हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री थीं, जबकि उनके पिता शोमू मुखर्जी फिल्म निर्माता थे। बचपन से ही उनके आसपास फिल्मों का माहौल था, लेकिन काजोल ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी बड़ी अभिनेत्री बनेंगी। काजोल ने साल 1992 में फिल्म बेखुदी से बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास सफल नहीं रही, लेकिन उनके अभिनय को नोटिस किया गया। इसके बाद साल 1993 में आई फिल्म बाजीगर ने उनकी किस्मत बदल दी। शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में उनकी जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया और काजोल रातोंरात स्टार बन गईं। इसके बाद काजोल ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। साल 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। सिमरन के किरदार ने उन्हें घर-घर पहचान दिलाई।

फिल्म बेताब के 43 साल पूरे होने पर सनी देओल ने अपने अभिनय सफर को किया याद

अभिनेता सनी देओल ने अभिनय की दुनिया में 43 साल पूरे कर लिए हैं। बुधवार को अभिनेता ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी डेब्यू फिल्म बेताब के 43 साल पूरे होने पर दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़ा क्लिप पोस्ट किया, जिसमें उनके साथ को-स्टार अमृता सिंह भी नजर आ रही हैं। सनी देओल ने अपनी इस पोस्ट के जरिए उन सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनके सफर में साथ दिया। अभिनेता ने लिखा, 43 साल पहले, बेताब से सिनेमा में मेरा सफर शुरू हुआ था। मुझे जो प्यार मिला और आज भी मिल रहा है, वह मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हर याद, हर फिल्म और हर उस इंसान का शुक्रगुजार हूं, जो इस सफर

का हिस्सा रहा है। आने वाले कई सालों, और कहानियों और प्यार का इंतजार है। साल 1983 में रिलीज हुई रोमांटिक-ड्रामा फिल्म बेताब से अभिनेता सनी देओल के साथ अभिनेत्री अमृता सिंह ने भी करियर की शुरुआत की थी। राहुल रवैल द्वारा निर्देशित और राहुल देव बर्मन (आर.डी. बर्मन) के संगीत से सजी यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई।

यह फिल्म साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी, जिसके बाद सनी देओल और अमृता सिंह रातों-रात स्टार बन गए थे। मूवी रिलीज होने के साथ-साथ इसके संगीत ने भी इतिहास रचा था, जिसे आर.डी. बर्मन ने तैयार किया था। जब हम जवान होंगे और जाने कहां गए वो दिन जैसे गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं।

भादाकुई में मां नर्मदा पुराण कथा के दौरान गौ सम्मान अभियान को मिला समर्थन

बेड़ापानी वाले गुरुजी ने हस्ताक्षर कर लोगों से अभियान से जुड़ने की अपील की

भादाकुई, भेरूंदा, सीहोर। ग्राम भादाकुई, तहसील भेरूंदा, जिला सीहोर में आयोजित मां नर्मदा पुराण कथा के दौरान गौ सम्मान आह्वान अभियान को व्यापक समर्थन मिला। इस अवसर पर बेड़ापानी वाले गुरुजी, मां भवानी के परम भक्त एवं मां नर्मदा पुराण पाठ के प्रसिद्ध कथावाचक ने गौ सम्मान आह्वान अभियान के समर्थन में हस्ताक्षर किए। उन्होंने श्रद्धालुओं से इस अभियान से अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील की।

गुरुजी एवं समिति ने किया भव्य स्वागत– गौ माता एवं मां नर्मदा की सेवा से प्रसन्न होकर आयोजन समिति एवं आदरणीय गुरुजी ने दो–दो बार आशीर्वचन के साथ पुष्प माला एवं गमछा पहनाकर अपने हाथों से स्वागत एवं सम्मान किया। इस दौरान श्री केवल राम राठौर जी को भी गुरुजी द्वारा दो बार गमछा उड़ाकर एवं हार माला पहनाकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। गुरुजी ने कहा कि गौ माता और मां नर्मदा की सेवा ही सच्ची सेवा है। उन्होंने सभी से गौ रक्षा और गौ संवर्धन के इस पुनीत कार्य में सहयोग करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और गौ सम्मान अभियान को अपना समर्थन दिया।

बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे राजस्व मंत्री

सीहोर। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत खेती एवं शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 07 अगस्त को दोपहर 12 बजे सीहोर स्थित कृषि उपज मंडी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राजस्व मंत्री शामिल होंगे। महोत्सव में जिले भर से किसानों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की भी गरिमामयी उपस्थिति रहेगी, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वर्चुअल माध्यम से किसानों को संबोधित करेंगे। बलराम कृषि महोत्सव के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा कृषि आधारित प्रदर्शनी एवं स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉलों पर किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों, उन्नत बीज, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, फसल विविधीकरण, सिंचाई तकनीकों, उद्यानिकी, पशुपालन तथा शासन की विभिन्न किसान कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही किसानों को योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया जाएगा। महोत्सव का प्रमुख आकर्षण कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों का मार्गदर्शन रहेगा। कृषि विशेषज्ञ वैज्ञानिक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जल संरक्षण, फसल सुरक्षा, उन्नत उत्पादन तकनीकों तथा बदलती जलवायु के अनुरूप कृषि प्रबंधन पर किसानों को व्यावहारिक जानकारी देंगे। किसान विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर अपनी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम में किसानों को नवीन कृषि तकनीकों को अपनाने, उत्पादन लागत कम करने तथा आय बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं, अनुदान, कृषि यंत्रीकरण एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में भी विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जिला प्रशासन ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होकर कृषि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन एवं शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। यह महोत्सव किसानों को आधुनिक एवं लाभकारी कृषि पद्धतियों से जोड़ने तथा कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण अवसर होगा।

पशुपालक ने पशु चिकित्सा अधिकारी पर अनियमितता के आरोप लगाते हुए एसडीएम से की शिकायत

खिरकिया। तहसील के ग्राम सारंगपुर निवासी एक पशुपालक ने खिरकिया पशु चिकित्सालय में पदस्थ पशु चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध शासकीय योजनाओं के संचालन में अनियमितता और कथित रूप से राशि मांगने के संबंध में एसडीएम को शिकायत सौंपकर जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। शिकायत सामने आने के बाद मामले की चर्चा क्षेत्र में हो रही है। वहीं संबंधित अधिकारी ने शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हुए उन्हें पूरी तरह निराधार और असत्य बताया है। शिकायतकर्ता ललित पिता राजेंद्र सारन ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि पशुपालन विभाग की विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को पारदर्शी तरीके से नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि योजनाओं से संबंधित आवेदन प्रक्रिया एवं लाभ वितरण में कथित रूप से मनमानी की जा रही है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनसे योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 10 हजार रुपये की मांग किए जाने की बात कही गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि राशि नहीं देने पर उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलने की बात कही गई। आवेदन में यह भी कहा गया है कि शासन द्वारा संचालित पशु उपचार, बीमा एवं अन्य योजनाएं पात्र हितग्राहियों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित की जानी चाहिए। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

इनका कहना:

सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह असत्य एवं निराधार हैं। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों को भी विभाग की योजनाओं का लाभ नियमानुसार उपलब्ध कराया गया है। डॉ. कुशवाह के अनुसार योजनाओं में निर्धारित अंशदान राशि नगद नहीं ली जाती, बल्कि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा होती है। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यवाही पूरी तरह नियमानुसार एवं पारदर्शी तरीके से की जाती है।

-पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय कुशवाह

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल: भेरूंदा के 25 अनुसूचित जाति के किसानों को झांसी में मिला प्रशिक्षण

» गौ-आधारित खेती से आय दोगुनी करने का दिया मंत्र

भेरूंदा, सीहोर। भारत सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से बुधनी विधानसभा क्षेत्र के भेरूंदा के अनुसूचित जाति वर्ग के 25 किसान भाइयों को कृषि प्रशिक्षण के लिए झांसी भेजा गया।

03 अगस्त से 05 अगस्त 2026 तक चला यह तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी और झांसी कृषि उद्यान में आयोजित हुआ। शिविर का मुख्य विषय गौ माता के माध्यम से दूध उत्पादन एवं कृषि आय में वृद्धि रखा गया था।

वैज्ञानिकों ने दी गौ–आधारित खेती की जानकारी– प्रशिक्षण के दौरान विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक खेती, गौ–आधारित उन्नत कृषि, वैज्ञानिक पशुपालन, दूध उत्पादन की आधुनिक तकनीक और स्वरोजगार के नए अवसरों के बारे में विस्तार से बताया। किसानों ने प्रशिक्षण में गहरी रुचि दिखाई।

शिवराज सिंह ने वीडियो कॉल से की बात– इस अवसर पर माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वीडियो कॉल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से सीधा संवाद किया। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनीं और उनसे गौ–आधारित प्राकृतिक खेती अपनाकर अपनी आय दोगुनी करने का आग्रह किया।

प्रमुख अतिथि एवं प्रमाण पत्र वितरण– कार्यक्रम में डॉ. एस.के. सिंह, कुलपति, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, डॉ. प्रमोद पाण्डेय, प्रशिक्षण सलाहकार, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय दतिया, डॉ. एस.के. सिंह, निदेशक प्रसार शिक्षा और समन्वयक डॉ. अंकिता रौतेला सहित आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

शिविर के अंत में सभी किसानों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

इन किसानों ने लिया लाभ– शिवनारायण बकरिया, विष्णु प्रसाद पाटील, सीताराम बरखाने, लक्ष्मी नारायण धावरे, रामविलास धनवारे, केवल राम बकोरिया, संतराम पेठारी, रामदेव पेठारी, रामदयाल पेठारी, देवाल बाकरिया, चंद्र सिंह, रामचंद्र मालवीय, विशाल मेहरा, सुदेश बाकरिया, इमारत पटेल, शुभम बाकरिया, दिनेश पेठारी, उमेश धनवारे, मुकेश पेठारी, आनंद बकोरिया, रामभरोस सोलंकी, गणेश पेठारी, अशोक मेहरा, सूरज मेहरा।

किसानों ने इस अवसर के लिए माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और आयोजन समिति का आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि इस प्रशिक्षण से खेती और पशुपालन में निश्चित ही प्रगति होगी।

यह संपूर्ण जानकारी प्रेस नोट जारी कर कैलाश धावरे, पार्षद, संयोजक, पूर्व प्रदेश कार्यकर्ता ने दी।

युवा मेहर मेर समाज संगठन ने बापू मालदेव राणा की जयंती मनाई

प्रदीप कुमार

मेहर शिरोमणि परम पूज्य बापू मालदेव राणा की जयंती के अवसर पर युवा मेहर मेर समाज संगठन बैरसिया द्वारा मधुरम पैलेस में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा बापू मालदेव राणा के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया ।

समाज के मेधावी छात्र-छात्राओं का किया सम्मान : मेहर समाज के होनहार विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा मंच से प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट अंक लाने वाले 17 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

एकता और शिक्षा पर दिया गया जोर : कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज की एकता, शिक्षा और युवाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि बच्चों की उपलब्धियों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने से उनमें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास बढ़ता है।

पांच सूत्रीय मांगों पर पटवारियों का मोर्चा, इटारसी में अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू

जिलाध्यक्ष देवेंद्र जाटव व संभाग अध्यक्ष कन्हैया लाल व्यास के नेतृत्व में तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की उठाई मांग

इटारसी। मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत तहसील शाखा इटारसी के पटवारियों ने वर्षों से लंबित पांच सूत्रीय मांगों के समर्थन में गुरुवार से अनिश्चितकालीन पूर्ण कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के पहले दिन जिलाध्यक्ष देवेंद्र जाटव एवं संभाग अध्यक्ष कन्हैया लाल व्यास के नेतृत्व में पटवारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार श्री रामशंकर झरबड़े को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र मांगों के निराकरण की मांग की।

संघ ने ज्ञापन में कहा कि लंबे समय से विभिन्न माध्यमों से शासन का ध्यान समस्याओं की ओर आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में दिए गए आश्वासन के बावजूद न तो पटवारी महाधिवेशन आयोजित हुआ और न ही लंबित मांगों का समाधान किया गया, जिससे पटवारी संवर्ग में असंतोष व्याप्त है।

पटवारी संघ की प्रमुख मांगों में कैडर रिव्यू लागू कर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ देना, नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा शीघ्र आयोजित करना, पटवारियों को जज प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में शामिल करना, विभिन्न योजनाओं के लंबित मानदेय का भुगतान तथा संघ पदाधिकारियों के स्थानांतरण नीति के विपरीत किए गए तबादलों को निरस्त करना शामिल है। इसके अलावा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित करने की भी मांग की गई है।

संघ ने बताया कि आंदोलन के पहले चरण में तीन दिवसीय सांकेतिक सामूहिक अवकाश तथा 20 से 23 जुलाई तक काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया गया था। इसके बाद 6 अगस्त से शासकीय व्हाट्सएप समूहों, वेबजीआईएस, सारा एप सहित सभी ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन पूर्ण कलमबंद हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि आंदोलन के दौरान किसी भी पटवारी के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई की गई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। साथ ही कहा कि हड़ताल के कारण किसानों एवं आमजन को होने वाली असुविधा की जिम्मेदारी शासन–प्रशासन की होगी।

भाजपा खेल प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी गठित

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश के खेल प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी का गठन प्रदेश संयोजक माननीय मानसिंह यादव जी द्वारा किया गया। नवगठित कार्यकारिणी में संगठन को और अधिक सुदृढ़ एवं सक्रिय बनाने के उद्देश्य से विभिन्न पदों पर अनुभवी एवं समर्पित कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे गए हैं। नई कार्यकारिणी में डॉ. विवेक सिंह परिहार को कार्यालय प्रभारी तथा डॉ. अनिल अग्रहरी को सह कार्यालय प्रभारी का महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान किया गया है। इस अवसर पर डॉ. विवेक सिंह परिहार एवं डॉ. अनिल अग्रहरी ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, तथा खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक माननीय मानसिंह यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, समर्पण एवं जिम्मेदारी के साथ किया जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को संगठन से जोड़ने तथा भाजपा की जनकल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए पूरी ऊर्जा एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे।भाजपा खेल प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने दोनों पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएँ देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में खेल प्रकोष्ठ संगठनात्मक दृष्टि से और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनेगा।

अतिथियों और स्वास्थ्य टीम ने मां के नाम पर लगाए पौधे

डॉ. प्रिया भावे चितावर के नेतृत्व में शक्ति नगर में मातृ शक्ति को समर्पित अनूठा पौधारोपण कार्यक्रम हुआ

भोपाल। नर्मदा मिशन की राष्ट्रीय संयोजक डॉ. प्रिया भावे चितावर के नेतृत्व में आज दिनांक 02 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे, शक्ति नगर स्थित दुर्गा स्टेज पर प्रकृति संरक्षण और मातृ सम्मान को समर्पित एक विशेष आयोजन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अपनी मां के नाम पर और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए पौधारोपण किया।

प्रमुख उपस्थित अतिथि एवं गणमान्य नागरिक सुरेन्द्र बाड़ीका (पार्षद, वार्ड क्रमांक 57 एवं पूर्व सदस्य, महापौर परिषद, भोपाल), अशोक पटेल, योगेश सक्सेना (गुड्डू भैया), दीपक उपाध्याय, संजीव उज्जैनकर, राजीव जोशी, दीपक सती, शीव यादव, परम लाल कनर्जी उपस्थित रहे। उपरोक्त सभी महानुभावों ने अपनी-अपनी माता जी के नाम पर पौधे रोपकर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में हर हेल्थ हॉस्पिटल की टीम का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान टीम के सदस्यों ने भी अपनी माताओं के नाम पर पौधारोपण कर अनूठा संदेश दिया। डॉ. नीतू मेहता (माता का नाम-श्रीमती मंजू कापरी), प्रशांत सराठे (माता का नाम- श्रीमती पुष्पा सराठे), अमित चौरसिया, चंदन कुमार पाल (माता का नाम-श्रीमती सोनी देवी), अमन शुक्ला कार्यक्रम के दौरान पार्षद सुरेंद्र बड़िका का विशेष सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिन्होंने सभी प्रतिभागियों के साथ मिलकर पर्यावरण संवर्द्धन और मातृ वंदना का यह संकल्प लिया।

एसडीईआरएफ के 90 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन , महानिदेशक ने वितरित किए प्रमाण-पत्र

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस के राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल (स्थश्रत्रस्न) में प्रतिनियुक्त जवानों के 90 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक समापन हुआ। समापन समारोह में महानिदेशक श्रीमती प्रज्ञा त्रह्मा श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले सभी जवानों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए तथा प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम तीन प्रशिक्षार्थियों को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए महानिदेशक श्रीमती प्रज्ञा त्रह्मा श्रीवास्तव ने कहा कि एसडीईआरएफ मध्यप्रदेशकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, जो आपदाओं के समय त्वरित एवं प्रभावी राहत-बचाव कार्यों के माध्यम से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण से जवानों की कार्यकुशलता, तकनीकी दक्षता एवं आपदा प्रतिक्रिया क्षमता में और अधिक वृद्धि होगी, जिससे वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से जनसेवा कर सकेंगे। उन्होंने प्रशिक्षार्थियों से प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान एवं कौशल का पूर्ण समर्पण और संवेदनशीलता के साथ जनहित में उपयोग करने का आह्वान किया। प्रशिक्षण में 44 जवानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसमें बाढ़ आपदा प्रबंधन, ध्वस्त संरचनाओं में खोज एवं बचाव , प्राथमिक उपचार , सीबीआरएन, आपदाओं में बचाव एवं प्रतिक्रिया सहित अन्य विशेषीकृत आपदा प्रबंधन तकनीकों का प्रशिक्षण शामिल रहा। प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद ये जवान एसडीईआरएफ की विशेष आपदा प्रतिक्रिया टीम के सदस्य के रूप में प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में अपनी सेवाएँ देंगे। शासन के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार उन्हें 50 प्रतिशत जोखिम भत्ता भी प्रदान किया जाएगा।

इस प्रशिक्षण की विशेष उपलब्धि भिंड जिले में आपदा राहत कार्य के दौरान शहीद हुए एसडीईआरएफ जवान की धर्मपत्नी श्रीमती डॉली कुशवाह की सहभागिता रही। उन्होंने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सेवा, साहस एवं समर्पण की प्रेरणादायी मिसाल प्रस्तुत की। उनका यह संकल्प राष्ट्रसेवा के प्रति अटूट निष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता का प्रतीक है। समारोह में उप पुलिस महानिरीक्षक श्री अमित सांधी, संभागीय सेनानी श्रीमती संगीता डी. कुमार, श्री कमलेंद्र परिहार सहित एसडीईआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्वामी प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक विनोद सिंह तोमर द्वारा प्रदेश वॉच मीडिया ग्रुप 11 प्रेस कॉम्प्लेक्स एमपी नगर जोन-1 भोपाल (म.प्र) से मुद्रित एवं 87, पुट्ठामिट गेट के सामने, छोला रोड, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश से प्रकाशित। संपादक : विनोद सिंह तोमर मो. 7067515898, स्थानीय- संपादक संजय सक्सेना RNI NO. MPHIN/2015/61965 (सभी विवादों का न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल न्यायालय के अंतर्गत ही मान्य होगा।)